

लि०, राधाबाब के मैनेजमेंट ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को, कलकत्ता भावनगर, बम्बई के रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को और गुजरात सरकार को पत्रों से, तारों से कई बार ध्यान खींचा है, तो भी इसका कोई परिणाम प्राया नहीं है। इससे यह सीमेंट उद्योग को, मजदूरों को और सरकार को नुकसान होता है, और सीमेंट की सप्लाई कम हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

- (2) स्टीम कोयले के अभाव से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के पोरबन्दर शहर में स्थित श्री जगदीश धायल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०, पोरबन्दर की वनस्पति उद्योग की फैक्टरी को भी प्रति दिन 10 टन के हिसाब से प्रति मास 300 टन स्टीम कोयले की जरूरत पड़ती है। इस इंडस्ट्री को 1-9-77 से 20-2-78 के दौरान सिर्फ 377 टन कोयला मिला था। अब यह वनस्पति इंडस्ट्री भी बन्द हो गई है। इसके मैनेजमेंट ने तारीख 13-2-78 से चीफ प्रोपर्टींग सुपरिन्टेंडेंट, ब्रिस्टन रेलवे, बम्बई को तारीख 8-2-78 से ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन (कोल), ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता को पत्रों से और 7-2-78 से तार से ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन (कोल) को कोयले के बैगनों को तुरन्त भेजने के बारे में ताकीद की थी तो भी रेलवे तंत्र ने कुछ किया नहीं।

- (3) इसी तरह पोरबन्दर के कैमिकल के बड़े उद्योग श्री सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, पोरबन्दर की भी स्टीम कोयले से बनती हुई बिबेसीयर की भी तंगी हो गई है।

इससे यह बड़ा उद्योग भी बन्द होने की स्थिति में था गया है।

- (4) सौराष्ट्र प्रदेश के मोरबी शहर में रूफिंग—टाइल्स बड़े पैमाने पर बन रही हैं, तो इन उद्योगों को भी जनवरी, 78 से स्टीम कोयले के बैगन न मिलने से बहुत रूफिंग टाइल्स के कारखाने बन्द हो गये हैं और प्रतिदिन बन्द हो रहे हैं। इससे 5,000 मजदूरों की रोजी का सबाल उठा है। इस उद्योग के एसोसियेशन ने भी भारत सरकार और गुजरात सरकार का ध्यान आकषित किया है, तो भी कुछ नहीं हुआ है।
- (5) बोड़े ही दिनों पहले पोरबन्दर की महाराणा कपड़ा-मिल स्टीम कोयले के अभाव से बन्द हो गई थी, फिर बोड़े कोयले के बैगन आने से चालू हो गई है, परन्तु अब इन्हें पूरे कोयले के बैगन मिलना जरूरी है ताकि नियमित रूप से चल सके।

तो हमारे उल्लिखित उद्योगों को नुरेस कोयले के बैगन प्राथमिकता से मिलें, ऐसा प्रबन्ध करने के लिये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय, और ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग और उद्योग मंत्रालय से मैं प्रार्थना करता हूँ।

SHRI RAGHAVJI (Vidisha): Sir, I have also given a notice under Rule 377.

MR. SPEAKER: All the notices received are considered; if you give today, it will be considered for tomorrow.

श्री राघवजी : चार दिन पहले दिया है।

12.45 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—
Contd.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING, AND
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION—Contd.

MR. SPEAKER: We will now take up discussion and Voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Works and Housing and the Ministry of Supply and Rehabilitation.

Shri Yuvraj. Please be brief. You have already taken more than eight minutes.

श्री युवराज (कटिहार) - अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ़ वर्क्स एंड हाउसिंग, धीर सप्लाय एंड रीहैबिलिटेशन की डिमांड्स पर धरना निवेदन करते हुए मैंने विभाग की गड़बड़ी की तरफ ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। वर्क्स विभाग के डिम्पे धांसिडेथ धीर टाउनशिप के निर्माण का काम है। करल एरियाथ में मकान बनाने का दायित्व स्टेट गवर्नमेंट्स पर है। धरधन एरियाथ में, झिल्ली धीर धन्य बड़े नगरों में, सरकारी कर्मचारियों के लिए धावास धीर बड़े बजटों के निर्माण का काम हाउसिंग विभाग द्वारा किया जाता है।

यह विभाग पालिसी, या कोऑर्डिनेशन, या कंस्ट्रक्शन या बजटिंग का काम करता है, लेकिन जिस ठंठ से पुरानी गवर्नमेंट-काम करती थी, उससे कुछ धन्य हट कर, कुछ रेडिकल थेंबिथ ला कर, यह विभाग धावास की समस्या को हल करने की बिना में कुछ कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं समझता है। दिल्ली शहर में लगभग 250 हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसायटियां हैं, जिन में से केवल कुछ ही सोसायटियां मकान बना पाई हैं। जो सोन-लोकल धीर रेंथ टू-थू हैं, वे तो धरना काम करा खेते हैं, लेकिन लो पेथ एम्प्लाइड धीर गरीब धादमियों की सोसायटियों को कोई मदद नहीं दी जाती है।

1959 में रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के एम्प्लाइड ने, जो साधारण सोन है, एक हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई। 1969 में—दस बरस के बाद—उसे 60 एकड़ जमीन धाकर की गई। इस

सोसायटी ने 14 लाख रुपया डिपॉजिट किया लेकिन इस के बावजूद उस का काम काज धाज तक पूरा नहीं हुआ है, धधरा पड़ा हुआ है। विभाग की धीर से कई धधधने धीर बाधायें डाली गई हैं। यह प्रयत्न नहीं किया गया है कि यह काम तीथ गति से हो। विभाग की धीर से धसहयोन ही हुआ है, कोई सहयोन नहीं मिला है। पिछली गवर्नमेंट के बल्ल में धार धार दका धाधासन दिये गये। जमीन का म्युटेसन भी हुआ, लेकिन धाज तक हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ धाकर्षित करना चाहता हूँ कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के इस साधारण एम्प्लाइड की कठिनाई को दूर करने के बजाये उस की उधेधा की गई है। सारे देश में यही झलत है। करल एरिया में तो गरीबों की हाथत धीर बजतर है। एक ने नेसनल हाउसिंग पालिसी इन्होंने बनायी धीर उध के मुताबिक यह तथ हुआ कि गरीब लोगों को 15 सौ रुपये दिए जायेंगे उसके बजट के मुताबिक। राज्य सरकार के द्वारा यह काम कराया जा रहा है। लेकिन धाप देखें कि हम सोन जो वैसे उनको वैसे उस वैसे का धुधयोन होला। इसलिये धाप जहां जहां—गरीबों के धावास की ध्यवस्था करें जहां वह उन्हें काइड में धे धीर करल एरिया में जो सामान मिले जैसे टाइल्स ई या ऐस्बेस्टस हैं, धकड़ी है, यह लेकर हम गरीबों को धे जिससे यह काम हो सके।

एक बात धीर कहना चाहूंगा। 1939 में जब लड़ाई छिड़ी थी उस बल्ल इन का एक विभाग प्रोक्पोर करने के लिए बना डायरेक्टर जनरल सप्लाय एंड डिस्पोजल का। वही विभाग तमाम सप्लाय का काम धाज की करता है। लड़ाई के जमाने में प्रोक्पोर करना धीर हिन्दुस्तान की चीजों को बाहर धेजना, वही-मुधय काम इस विभाग का था। उस समय जो बड़े बड़े ठेकेदार थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथन थे धीर उन को लाल सप्लाय करते थे उन्होंने कपेकों रुपया कमाया। जब लड़ाई

कर्म हो गईं तो डिस्पोजल का काम भी उन लोगों ने किया। वही विभाग प्राज भी बना हुआ है। जो बड़ी बड़ी खरीद होती वह उस के द्वारा होगी। वह सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें सप्लाय करते हैं और उस से तमाम सड़कें थोडाला सम्पूर्ण देश में हो रहा है। रेलवे में, पी एंड टी में और दूसरे कुछ विभागों में धन्य सप्लाय का काम होता है। जो मेरा कहना यह है कि यह डिस्पोजल-अनरल सप्लाय एंड डिस्पोजल का विभाग रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिलकुल इसमें कंटेन्टेशन हो रहा है और कम्प्लेन बढ़ रहा है। इसको तोड़ने की जरूरत है। इन बच्चों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : पहले धन्य-कर्म करते हैं और फिर भाषण करते हैं।

श्री कुराब : 18 जुलाई, 1977 को श्री सबन माल कपूर ने एक प्रश्न किया था— कि अतारहित प्रश्न संख्या 3811, उस का उत्तर काफ़ी असन्तोषजनक प्राया। उन्होंने कई बार उस के लिए किट्टी लिखी। उस का केवल ऐकनाते प्रमेट किया गया, केवल-रत्न-प्रदायगी के लिए जवाब दिये गए लेकिन उस का कोई हत नहीं निकाला गया। इस तरह हम जो समस्याएँ उन के सामने रखने उन का कोई हम नहीं सोचा जाएगा, कोई उस के लिए रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो हमारी कठिनाई बढ़ेगी। इन बच्चों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): At the very outset I will raise certain points to which, I hope, the Minister will pay his attention.

In this report of the Housing Ministry it is said that housing facilities will be provided to the employees, etc. While formulating the housing policy I request the Minister to make necessary provision for accelerating provision of housing facilities to the poorer persons in the rural areas because the poorer sections of our society like the

landless peasants have no shelter to live under. So if any provision is made for their purpose, at least they will be benefited and the country like ours will be benefited.

Again, I think the Ministry is very keen regarding clearance of the slums or improvement of the slums. But when I remember Calcutta, the thousands of slums which are there come to my mind and can you imagine, Sir, that civilised persons in this 20th century are living in these areas? The slums are in such a condition that man cannot live there. What steps have so far been taken by the government—I cannot understand. So I urge upon this Ministry the immediate necessity of paying attention to these slums because during the 30 years of Congress regime, it is found that nothing has been done for them. And no improvement is there. So, I request the hon. Minister to take necessary steps to clear the slums immediately.

13 hrs.

I want to mention here that after thirty years of Congress regime they mentioned 'talk less, work more'. But it was detected by the people that that was a hollow slogan. That is why they have driven them out. I want to request the Minister to make a note of it, improve the position and clear the slums so that people can live in a proper manner.

It is stated in the report that there is a provision of funds and the employees will be given necessary advance for the construction of houses. But there are so many difficulties—that after the submission of the application lot of time lapses and no response is given by the Department. A lucky few do receive money but by that time the cost of building material rises. That is why the advance given to them cannot satisfy their demand or requirement. I hope that the Minister will make a note of it. I suggest, let the Ministry take the responsibility of the construction of the buildings if the Government has good wishes for them.

Additional money should be provided to the employees who are in difficulty because the cost of material has gone up.

In the Report, I feel, something wrong has been mentioned and there is something contradictory. The Report says:

"The year 1977-78 brought new hopes and promises in tackling the continuing promises to refugees and repatriats. The Department of Rehabilitation geared itself to the task of accelerated implementation of rehabilitation schemes and relief operation with the major thrust on the economic rehabilitation of the displaced persons and repatriats and their integration into national economy."

I think it is contradictory. I think thousands of refugees are coming from Manna, Madam, Dandakaraniya and other places. They are creating problems in West Bengal. If such a report is given, I think there is something wrong.

There are reports of corruption against the bureaucrats in Manna and Dandakaraniya. That should be looked into. I think that the Minister will take necessary steps so that corruption can be stopped.

In Delhi also I see there are thousands of refugees. I had an opportunity to go to Chittaranjan Park. There are thousands of refugees living here and there in Delhi. They are asking for shelter but they are not getting shelter. They have not yet been rehabilitated. Although it is stated in the Act of 1948—those who are gainfully employed in Delhi or anywhere else in India will be rehabilitated soon—yet they are not rehabilitated. I think the Minister will take necessary steps for their settlement at least. It is alleged that uniformity is not there in the case of determination of acquisition cost and the development cost; the manner of determination of cost which has been adopted in the case of Kalkaji is not adopted in the case of Chittaranjan

area. I request the hon. Minister to take note of this and to rectify this anomaly.

The refugees had deserted their camps and they have sold out their belongings. Now Government is making arrangements for them to come back. I request the Department and the Ministry concerned to see that their belongings should be given back to them. Necessary financial assistance for resettlement should be given to them.

Some of our Congress friends have alleged that the West Bengal Government is doing nothing. But, Sir, it is only the Congress which has created this refugee problem. I hope that the Janata Government will take necessary steps for solving this problem.

Then, Sir, in regard to the Department of Supply I wish to submit that there is a decreasing trend in the matter of purchase of products of the Khadi and cottage and small scale industries. This should be set right. I am not going into the details as I do not have time. I hope that necessary steps will be taken by the hon. Minister in this regard.

Then, Sir, regarding Hindi, the Report says that arrangements have been made for the propagation of Hindi. May I ask the Minister through you, Sir, whether the Department of Supply has been given the authority to propagate Hindi? Whenever I see propagation of Hindi, Hindi workshop, cash award scheme, publication and terminology, etc., I also want to see that necessary steps are taken also in respect of the other regional languages.

In conclusion, I would like to submit that the Ministry should not create any confusion among the people and they should not pressurise Hindi among the people of the different languages. Hindi can be introduced only by the understanding on the part of the people.

Sir, with these words I conclude. I support these Demands for Grants.

SHRI SAMAR GUHA (Contd.): Mr. Speaker Sir, an impression created by the Ministry of Rehabilitation on various occasions in this House and also outside that there is not much residual problem for the refugees to get them rehabilitated. You will remember, I tried to raise this issue on several occasions and even in this session of Lok Sabha. Earlier I had raised it on innumerable occasions. Every time an impression was created that it is a Ministry just preparing itself to wind up because this Rehabilitation Department appeared to the Government and perhaps to the Minister concerned also as nothing but a redundant department or just a burden on them. There is a sudden eruption of the refugee on rush. you can call it a re-influx by the deserters, as they call them from the rehabilitation sites. It has created a new awareness, a kind of horror also, in the mind of the Government, not only in the mind of the Central Government, but other State Governments as well, about the problem of refugees and their rehabilitation.

11.00 hrs.

[**SHRI DEHENDRANATH BASU** in the Chair]

Sir, it appears to me that neither the Central Government nor the Government of West Bengal nor the Government of Orissa nor the other Governments which are concerned with the problems of the rehabilitation of the refugees in Dandakaranya area have adequate minds, hearts, feelings or understanding of the problems of the rehabilitation of the refugees.

If it had been so, some of the Central Ministers or, at least the Rehabilitation Minister could have once visited the rehabilitation site. At least one of the Ministers or, if not the Chief Minister, at least, the Minister of Rehabilitation of West Bengal should have visited much earlier before the rehabilitation of refugees started. At least one of the refugee Ministers from Orissa should have visited

that place. Dandakaranya is part of Orissa. They have got innumerable officers there who are indirectly involved.

None showed any, if I may use the word, understanding or feeling in the hearts or minds, for the proper rehabilitation of the refugees. Sir, you will remember, this House will remember that even during this session and even earlier session too, I tried to draw the attention of the hon. Minister about the necessity of sending a team of Members of Parliament to enquire into the conditions of refugees living in different camps and also in different refugee sites and also I had asked him to probe into the probability of the settlement of the refugees in the Andaman islands. But, Sir, unfortunately, it was bluntly refused by the hon. Minister. If the caution I had given earlier was taken notice of, perhaps, the situation that has developed would not have arisen.

Sir, the House is very thin now. But, we saw on innumerable occasions in this House, explosion of tempers, explosion of anger whenever any issue arose about the atrocities committed on harijans, scheduled castes or about their problems. But, I want to draw the attention of the House, and, through the thin House, perhaps, it will go outside, to the people at large, that these unfortunate refugees are awaiting rehabilitation for 10 or 15 years—1,30,000 refugees were in Deoli, Mana and other camps—and the refugees in Dandakaranya Area those who had been rehabilitated in Dandakaranya, seventy to eighty per cent of them, belong to harijans or scheduled castes. At least I expect Babu Jagjivan Ram to issue a statement in sympathy with the present plight of the refugees who have gone out of Dandakaranya and who are still rotting in different camps and are facing a miserable situation in the sites which are called 'rehabilitation sites' without scope and necessary facilities for their economic rehabilitation. What a horrible scene it is! The hon. Minister has not gone there. Some of the

Ministers should have gone to West Bengal to see what a horrible sight it is. If there is one definition, it is a human hell if I am permitted to use the word. It is a scene of real human hell in Hastnara area of West Bengal just bordering the Sunderbans area where there are about 20,000 people. Nobody knows what it is. According to West Bengal figures the number of deserters is only 35,000. From the report in the press, it is about 8,000 people who are waiting in Waltair station and 5,000 in Koraput area. What a horrible scene it is—I used the words 'human hell'. What more hell it can be? There is no shelter; there is no relief arrangement; there is no food and there is no adequate medical facility. Sir, you know in this season there are hail storms, strong winds and what a miserable condition they are facing there. It is also not known to many Delhi papers because they do not carry that miserable situation that has been created in West Bengal. Everyday about a dozen people are dying like cats and dogs. They have no money to purchase wood so that they can burn their dead bodies. Dead bodies are thrown in the river Ishamati. West Bengal government is now saying many things but they should make a heart-search of their own also. We all—whether in the Opposition or in the Congress—tried to exploit refugees for political purposes. The present West Bengal Government is not above that complaint. They exploited them. They utilised them for political purposes. Let us not forget these parties who have formed the Government—my party was also there at that time excepting me—did not want that the refugees should go out of West Bengal. They did not want that they should be rehabilitated in Dandakaranya. They did not want that they should be rehabilitated in Andamans. Now, the hon'ble Minister is harry about Andamans but at that time Andamans was included in the territory of West Bengal. If Bidhan Chandra Roy wanted he could get rehabilitation

done there. He could send as many refugees if he wanted to send there. At that time these Leftist friends—mine was the lonely voice—did not want the refugees to go to Andamans and other areas where adequate provision can be made for rehabilitation. Now, how heartlessly they are behaving. They are using police everywhere. If people are getting into Sunderbans area either by train or by boat or by trucks they are mercilessly beaten, thrown out and all their belongings are snatched away. They are being treated as costs and dogs and sent back to Koraput area. What is the result! Again they are coming back. You send them in tens and come back in hundreds. Why is it so! Brains are being utilised... intelligence brains. Why? They say saboteurs are working. They say agent provocateurs are working; some political agents are working. I say, some commonsense should be left with us. Even if one ex-Mondal whose name has been mentioned, nobody can say what it is. This is only an assumption that some conspiracy is working behind. If you have some commonsense to understand these people—cent per cent of them—are cultivators. They are not to be easily swayed by cheap propaganda. For years together nobody has cared to enquire into the basic cause and basic reasons. No responsible person has even cared to go to Dandakaranya to know as to what their problems are. We are getting letters and letters. Many a time we have demanded on the Floor of the House for a team of Members of Parliament to be sent there but nobody cared. Now, their grievances are accumulated. As it happens in the case of a flood when the bundh is broken like a surge of a flood without having any consideration of the consequences that they will have to face they are coming out. They have sold out their houses, their belongings and their bullocks. They have now become desperate. They say we will not go back. Even if we are to die we will die. Do you think some—agent

provocateur, or some political instigator can create that kind of fanatic attitude in the mind of the people unless there is some basic fundamental reason to goad them to that situation of desperation where life is—if there is anything most valuable for a person it is life—they have come out of their, I should say, rehabilitation sites... To go where, they do not know..... aimlessly? They do not know where to go and what will happen? They have no money, they have no clothing, they have no shelter. Therefore, I would make an appeal to the Prime Minister that now the situation has developed to such a pass in the crisis that it will not be possible for any Minister either the Rehabilitation Minister, the Minister of West Bengal or the Minister of Orissa you tackle this problem. The dimension and magnitude of this problem has assumed a serious proportion. I warn the Central Government to keep this in mind that it is not only a human problem but these people are coming out in hundreds and thousands and much more than that the area where the refugees have been concentrating has already crossed 35,000 mark and more are coming. They say that there are about 40,000 deserters. These are press figures. I do not know. It is not only a human problem, but the people will be dying and are dying in hundreds. It is a serious law and order situation which is likely to develop in West Bengal. Particularly, in that area, already there is a conflict between the local people and the refugees.

13.22 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

And I warn this Government that the majority of the local people there are the Muslims and if it takes an ugly turn of a different type, we do not know where it will end because if the Hindus and Muslims of the local inhabitants are united against the refugees, we do not know what they will do. They are trying to forcibly occupy the schools and every shelter place in the area. Therefore, this

situation has to be tackled very seriously and expeditiously. I had a talk with the Prime Minister. I made a request to the Prime Minister and I will again make an appeal to him, to this House, to tackle the problem expeditiously and quickly with a human consideration and compassion, with an understanding, with a feeling for the problems of the refugees. Let this Government and the country not forget that there are a set of criminals. If they are the by-product, they are the by-product of the national crime that we committed on them. They did not go out of their own. If there is any definition for the word proletarians, an actual definition, they are the worst type of proletarian. They have lost their human heart, everything they have lost. In the case of West Bengal refugees, they got compensation. But in the case of East Pakistan refugees they have not got a farthing as compensation. Their lands, their belongings, everything they left there. I would make a request to the Prime Minister to immediately go to Karaput area; convene a meeting of the Chief Ministers of West Bengal, Orissa and the Rehabilitation Minister of West Bengal, the Rehabilitation Minister of Orissa and the Rehabilitation Minister of the Central Government to find out ways and means to tackle this problem. Firstly, I should ask the Government not to try in a way as they are attempting to just huddle them together, bundle them together and pack them off in a train like cattle. This is not a way of doing things. Firstly, temporary shelter, if you can call it a shelter, should be built up and adequate medical and other relief should be given to them. These Ministers should sit together and try to resolve the problems. Some kind of high officials, Committee call it officials or Members of Parliament, whatever form, it should be an effective machinery, has to be devised to enquire into the problems and find out why these people left their rehabilitation camps

[Shri Samar Guha]

in such large numbers, almost like an avalanche and then persuade them, convince them that there is no place for them in West Bengal. It is a fact that they will turn only into a community of beggars in thousands. They will have to go back. But for that, a psychological condition has to be created. Do not utter heartlessly, do not give it to the press saying that they will not be given again rehabilitation benefit. This is a heartless way of expressing things and I may call it a tactless way of dealing with the problem. You have to treat the whole problem with a human consideration and human compassion.

Then I have to say a few words in the larger context of the refugee rehabilitation. It is not that the people are living only in the Malkangiri area. They are still in other places also. I said that about 1,30,000 refugees had been in different camps for the last 10 to 15 years. Because it is in the mind of the Rehabilitation Minister that the Rehabilitation Department has to wind up more quickly without giving proper consideration, whether their rehabilitation will be backed by proper condition of economic rehabilitation? They have been hurriedly sent to different sites. Perhaps the hon. Minister had had no time or opportunity to know that so many refugees were sent to Bihar and other areas; there were miserable pitiable stories, people were thrown in those areas with no facility, no possibility whatever for economic rehabilitation. Those people deserted in thousands and added to the thousands of beggars, beggar community in West Bengal. In this background I raised on the floor of the House the question of rehabilitation of refugees in Andamans. There was a high powered team constituted by the Central Government with secretaries of almost all the departments.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR

BAKHT): How many families could be sent there?

SHRI SAMAR GUHA: I will reply to this question later on. The Secretaries of the planning department, Home Ministry, Finance ministry, Rehabilitation Ministry all these secretaries were constituted into a committee, after many months of sittings in Delhi they surveyed all the areas and Andamans and they made a report to the Central Government that by 1976, 75,000 refugees could be and in 1968 the then Home Minister sent a study team of Parliament and I was one of the members and I saw with my own eyes what was happening there. The Committee of secretaries made a field of survey and after making all kinds of surveys, had made this recommendation; if you want I shall show it tomorrow; it is in print and I have read out the relevant part of that report in the House that by 1976, 75,000 refugees could and should be rehabilitated. I have seen many areas were being cleared.

But for different reasons, for political considerations, the commitment that was made in this House by the earlier government on the basis of the field survey report by the highest ever committee that was formed, had been denied. I had a talk with the Prime Minister and I found that the government had not taken a decision to wind up the rehabilitation department nor has the government taken a decision that no refugee should be sent to Andamans. The Prime Minister says: there is scope and possibility; we shall explore it. But I do not know what has happened to the hon. Minister. Whenever this question is raised almost as a super command of the military general, he says: no single refugee from West Bengal can be sent to Andaman Island. The Prime Minister's views are different even today morning I had a talk with him.

In conclusion I should say that the sinners are not the refugees; it is a political and national sin and they are the victims of that sin. I should

also remind you that if any part of our country could claim that it has made the largest quantum of sacrifice and contribution to the freedom struggle, East Bengal can claim it. You will not find a single family in East Bengal, those who are now refugees, whose one or two family members had not spent 5, 10, 15 years in jail; there were two revolutionary centres of Jugantar; there was the headquarters at Dacca.

There is not a single jail in East Bengal which does not know the history of the martyrs who had been hanged in jail. I will again say that if there was any place in India, where there has been the least communal tension, communal feeling and the best relationship between the Hindus and the Muslims, it was in East Bengal. There had been communal riots, but they were inspired and instigated by the Britishers in those times to suppress their revolution movement. They are the victims of the political conspiracy. Keep it in mind. It is the responsibility of the Central Government, it is the responsibility that devolves on us on the basis of sacred commitment, sacred pledge that was given to the people who have been—if I may use a strong word—betrayed or who are the victims of the unfortunate and tragic circumstances of partition. I would only request finally that let the Rehabilitation Ministry work with a heart, with a mind, with a feeling and understanding of the problems of rehabilitation of the refugees, not only with compassion, but with necessary national perspective.

*SHRI S. K. SARKAR (Joyngar):
Mr. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the demands of the Ministry of Rehabilitation and this I am doing with great pain in my heart. In my area, Hasnabad, 25000 refugees have come to take shelter under the bare sky from Dandakaranya. I have no words to describe the woeful condition under which they are living and it

would be a matter of great satisfaction if some one from the Centre goes to see for themselves, the plight of those unfortunate people. It is with great regret that I am to say Sir that the Central Government has shown no sympathy for the solution of this problem. The State Government's reaction to the problem amounts to sending the refugee back to Dandakaranya. Of course it is a debateable point whether with the meagre resources the State Government all by itself would be able to tackle the problem or not, but there can be no denying of the fact that all the Bengalis feel hurt and frustrated at the attitude of the Central Government towards this problem. It is unbelievable how the central leadership can think of evading the responsibility in this regard. Mr. Deputy Speaker Sir, if we go through the history of the freedom struggle of our country and if one is to single out (one single and) maximum contribution made by one segment of the population then the honour would necessarily go to the people of Bengal particularly with East Bengal. It cannot be denied Sir that one out of three families in East-Bengal had to suffer torture and even had to go to jail for their participation in the freedom struggle and it is really sad and lamentable that Central leadership should try to forget the contribution of these people. Central leadership is trying to forget to pay all the debt that they owe to these people. The persons who are wielding power from the high pedestal of authority of the Central Government in Delhi are trying to forget to pay all the debt but I must warn and warn solemnly that if we forget to acknowledge the contribution of these people we have to pay heavily for this. Today we are playing with the fates of these people. No, I should say we are playing a game of chess. There is no parallel to the sacrifices that the Bengalis had made far attaining the freedom of the country. Today of all the rehabilitation sites that are there

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri S. K. Sarkar]

in Andaman, Koraput, Bihar, Betla, surely Dandakaranya is the worst place of rehabilitation that we have chosen for these people. It is very difficult for every human being to leave his motherland his home and hearth and I fail to understand why the Central analyse leadership cannot understand this human sentiment and they should take long to why these people are deserting their camps. However, it is a matter of great satisfaction that the Prime Minister has given an assurance that he will personally look into the matter and if necessary he will make an on the spot inquiry and will appeal to the refugees to go back to Dandakaranya. I wish him a long life and I wish him all success. But it is a matter of great regret that Shri Sikander Bakht who is heading the Ministry of Rehabilitation has not said a single word which can enthuse these refugees. We cannot forget the fact that at the time of partition the then national leaders had given a solemn assurance that minorities coming from East Bengal and West Pakistan would be protected by the Government of India. What does it mean? What does the word protection mean? Obviously it means that the Government of India will give them the right to live in this country. They will be rehabilitated here. But what has happened to that assurance. We had entered into a pact with Pakistan it was the pact we are trying to avoid the issue. Even today I find the same attitude prevailing with the Central Government who are only trying to bypass the real issue but I must say and warn the Government that if they try to avoid this issue in the manner the earlier Government had done then history will record it to be great betrayal. Mr. Deputy Speaker Sir, I think there is some sort of conspiracy in the matter. The Government heard by Indira Gandhi had amended the term refugee rehabilitation and they had only kept the word rehabilitation. Not only this the State Government headed by Shri Siddhartha Ehanekar Ray had given an impression to the country that the problem of rehabilitation of refugees

was over and consequently he had seen to it that department of Rehabilitation was wound up. I therefore feel that there was a conspiracy that was hatched between the Central Government (not the present Government) and then State Government to deal with the issue in such a nonserious manner. But I think a time has come when State Government and the Central Government must fulfil the assurance that was given to the refugees at the time of the partition of our country and that solemn assurance must be fulfilled at all costs. They must be given assurance that India is their homeland and if we are not able to do it we shall doing a great injustice to them. A great calamity is facing the country today and if we are not aware of it and if we do not become conscious of the dangerous situation that is growing then I must say Mr. Deputy Speaker Sir that a time will come when it would be beyond the power of the Government to tackle the situation. Today the refugees are not only coming from Dandakaranya but large number of minorities from the erstwhile East Bengal which was a part of Pakistan and today is being called Bangladesh are anxiously trying to cross over to India. In fact streams of people are coming every day by crossing over the border. On the other hand if the Central Government feel that by sealing the border they are going to solve the problem happily then I must tell them and warn them that we are being allowed to live in fools paradise. Sir it is a fact that every day 200 to 300 minorities are crossing over to West Bengal every day. The BSF are inflicting inhuman torture and firing on the refugees. To try to drive away these minorities from our border through torture and firing is in my opinion, no solution of the problem. What right the Central Government have I ask you Mr. Deputy Speaker Sir to break the promise that was given to the minorities of East Bengal that they would be protected by the Government of India when they come over to this country. What right the

Central Government has to break this solemn promise and if this BSF is acting so ruthlessly with these minorities. I must say they are acting against the law because it was a solemn promise given by the Government at the time of partition and that promise is being broken by the BSF. I must place them on the dock and charge them for the violation of the law and for the violation of solemn promise that was given to the minorities of the then East Bengal. The State of West Bengal is a small State which has manifold problems. It is already over populated and if over and above if refugees start pouring into the State from all directions then we will be crushed under the burden of such a colossal problem. Our social order has crumbled under such pressure, our economic order has crumbled and today we are pacing towards extinction. At this juncture if we do not take lesson of history then we will only have to face the consequences. Our Hindu brethren from Bangladesh are being forced to come over to India. Their life, property and self-respect today is in danger. I have my relations in Bangladesh. I very often get letters from them. These letters make pitiable reading of the situation under which the Hindu minorities are living in Bangladesh. I have no doubt in my mind Sir that the day is not far off when the Hindu minorities of Bangladesh would be forced to come to India once again. If that situation arises what shall we do? Are we to keep our doors closed to them or we to drive them back and push them deep into the territory of Bangladesh. Are we to welcome them with bullets and shower machine guns bullets on them? What are we going to do with them? This is a serious problem and surely we cannot keep our eyes shut. If we really do it then I must say that we would be living in the fools paradise. In order to tackle this problem it is imperative that the Rehabilitation Department must assign top priority to this problem, treat it as a national

problem and try to solve it with all sincerity and urgency that such a situation demands. Any lukewarm approach to this matter would be suicidal and therefore we the representatives of West Bengal in this House appeals to the Minister that he should rise to the occasion and give the problem a serious thought that it deserves and not try to deal it lightly because it is very serious matter and is pregnant with serious consequences.

Today a very explosive situation is developing in West Bengal where a new movement is going on in the State. The movement is termed as new home land in East Bengal. However illogical the demand may be but the human appeal that is inherent in it is important and Government can ignore it only at its own peril. They would be playing with fire; they would be playing with live bombs. Sir, it is quite immaterial whether the movement has my personal support or not but if the Central Government can support the demand of the Arabs for a home land in Palestine in the world forum of UNO, then certainly these persons—the minorities that are trying to come over to India and the refugees that are already here have a legitimate claim for a home land of their own. These persons have a right to live. These persons have a right to claim a home land. This home land must be created in the erstwhile East Bengal and if that cannot be done surely it must be on our own side of West Bengal and the Central Government must share all financial responsibilities for setting up this home land. If we fail in our efforts then we shall be playing with fire and we would never be able to suppress the exclusive movement that is growing slowly but surely. I would conclude my speech by quoting excerpts from a report prepared by Mr. Tariq Ali in support of my plea. Mr. Deputy Speaker Sir, you might be knowing that Mr. Tariq Ali is a Pak. citizen

[Shri S. K. Sarker]

who is presently living in London and is a noted Naxalite leader. In his publication "Explosion in the Sub-Continent" which was written in 1973 he writes and I quote:

"It has to be understood that the objective conditions in West Bengal today are such that the Congress Government will not be able to bring about any marked changes in the situation."

"It is obvious that any strategy for West Bengal has to take into account the existence of Bangladesh and the struggle of the Left in that country. The right of the Bengali people to national self-determination cannot simply be confined to East Bengal and, therefore, a strategy has to be developed in terms of a united socialist Bengal and a co-ordinated struggle launched."

"Bengal, historically in the vanguard of the anti British imperialist struggle, the area which gave birth to the Indian revolutionary movement, may once again play a pilot role."

As a peace loving citizen of this country I must say that if the peace of our country, the culture of our country and democratic values of our country are to be retained and nurtured then the problem of the refugees is to be given the top most priority it must be considered a national problem and tackled on a war footing. I must with the folded hands appeal to the hon. Minister Shri Sikander Bakht that he should try to tackle the issue not in a light hearted manner even when I support the demands I record my anguish and my grief that I feel about the unfortunate refugees who the victims of circumstances to whom we owe a lot.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU
(Chittoor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, housing is a great problem in this

country not only in the cities but also in the villages. According to the statistics given by the Government, the requirement in the urban areas is 3.8 million units and in rural areas 11.8 million units. It is also stated here that 50 per cent of them will be one-room tenements. Therefore, they should be given facilities for construction of tenements which will have more space. Now in the rural areas five or six families live in a thatched hut. Therefore, the problem of housing in the rural areas is more acute and should be given more attention.

It is true that Government have some schemes for rural housing. One is housing for weaker sections. But that is not satisfactory. Even though there is reference in the report to the construction of 11.8 million units in the rural areas, there is no programme or any scheme. First of all, people must be given house sites. If we go by the statistics given in this booklet, only 60 per cent of the population in the rural areas have been given house sites. It is quite necessary to give house sites to the other people also without much delay. It should be done within a period of three or four years. But, unfortunately, neither is there any scheme for it nor is any finance provided for it. So, I would say that the Minister must allocate more funds for providing house sites in the rural areas.

With regard to the construction of houses, though it is mentioned that subsidies and loans would be given, no amount is specified with regard to subsidy. The weaker sections like harijans and other backward communities are very poor and they will not be able to construct houses without substantial subsidy from the Government.

In Andhra Pradesh the State Government was able to construct 75,000 houses. In Kerala also they have made some progress in this direction. But the difficulty is that they go by a type design, for which they give a loan of Rs. 1,800 to the poor people. That

design is not suitable because the space is too small. So, why not conduct some research and see whether thatched huts or some other modes of construction of houses could not be suggested to them. Even then, a major portion of the money is eaten away by the contractors and the poor people are not benefited. Unless there is participation of the poor people in the construction of those houses, unless the poor people are given permission to build houses the way they like, to suit their needs and requirements, no scheme will be successful. Now what happens in most of the houses for the poor is that two or three couples live in the same house. So, the space must be more to meet the needs of the large number of members in those houses. If those houses are constructed according to a type design, even one family will find it difficult to stay there. So, these people must be allowed to choose their own designs and construct the houses in the way they like.

Rural housing provides not only houses to the needy people but also employment in the rural areas, where there is acute unemployment. In many of the countries they take to housing to solve the unemployment problem. Likewise, we should also go in for housing on a large scale so that the people in the rural areas are provided more employment.

So far as bank loans are concerned, the banks are not co-operating either with the Government or with the people. That is why I say that the Government should have greater control over the banks. They should be asked to allocate funds for housing schemes. For example, in my constituency of Chittoor, the barbers formed a co-operative society and house sites have been given to them. Since they have got permanent income, they can very easily repay the loans. But the banks are not giving them loans. So, either the Government should make it mandatory in the banks to provide loans to these people or alternatively the Government should stand guarantee to the

banks when the banks provide loans to the co-operative housing societies of the weaker sections.

There should be intensive research to develop designs suited to the rural areas. For example, research can be done on how the mud walls can be made to stand for a longer time, especially in project areas. Because the mud is so soft, it will not stand longer. Research should be conducted to see how it can be strengthened. This is very necessary because it is not possible to get either brick or stone in the rural areas.

Coming to water supply, it is mentioned that though there are 3,119 towns above the city level, only 1,890 towns are having supply of water. Even in those towns where there is supply of water, as the Minister knows only too well, it is not sufficient. The Minister also knows that the population in the towns is increasing and that the villages are coming up. So, Government should plan ahead. With the increase of population, water supply should also increase. I know that in many towns, especially in Andhra Pradesh, no survey has been conducted of ground water and also surface water which can be utilised. So, surveys have to be conducted in cities with regard to ground water as well as surface water which is available nearby.

With regard to rural water supply, out of 5,75,936 villages, only 65,000 are having piped water or tubewells. Many villages are not having even drinking water. If we want to provide only piped water, it is very difficult because a revenue village consists not only of the village but of so many hamlets with 10, 15 or 30 houses. They also require water. There are problem villages also where there is brackish water, where it is very difficult to get water even at a depth of 150 feet. There are areas like Prakasam District where there is fluoride in water. In Neyveli and in parts of Rajasthan, water contains sulphur. How to get good water in these tracts? There is saline water also in many

[Shri P. Rajagopal Naidu]

places. These are problem areas, and these problems have to be solved. For that research has to be conducted in desalination and also to make the water free of its sulphur content etc. To provide piped water may be very difficult. We have to find out other means.

Rigs are being supplied. They must be utilised, but they are not sufficient. Though the rigs are there, there are no resistivity meters to find out whether there is ground water or not. So, when the rigs are operated, they meet with failure and much loss is incurred. Without these meters, there is no use operating the rigs. The pipes and pumps given with the rigs for operating them are not working properly. For example, in the previous Assembly constituency of Bangarpalayam, which is in my constituency, 130 bores have been made and the pumps have been fitted, but only 15 or 20 of them are working because the models are not good. The make should be stronger. The rural people have to operate them, but they are not withstanding the pressure on them. Therefore, the models should be changed; otherwise, there is no use. For every bore we are spending Rs. 5,000. For 130 bores some lakhs have been spent, but what is the use? We are not able to dig wells because wells can go up to 60 feet, beyond that it is not possible; but in areas with scanty rainfall like Anantapur and other districts, we have to go up 100 feet deep. It is impossible to dig wells to such depths and hence bores are necessary. If bores are necessary, the pumps should be very strong so as to withstand the pressure put on them.

With regard to roads, I want to say one thing. Cyclone came to Tamil Nadu and affected Andhra Pradesh, but we were not able to give any help to the people in the coastal areas because there were no roads there. The Andhra Pradesh Government has proposed a highway along the coastal line. I do not know whether it has reached the Centre or not. Therefore, unless we

develop roads, it will not be possible to help the coastal people.

With regard to development of cities, I want to make only two suggestions. We have not divided our cities and towns into zones. Industries are everywhere in every city and town, and there is great pollution and people are finding it very difficult to live there. Therefore, cities should be divided into industrial zones. We do not have zonal laws. Zonal laws should also be there. Unless these things are there, we can prevent our cities from pollution.

Beautification of cities must also be there. In certain other countries, there are separate organisations for that purpose. They levy a cess to beautify the cities. But here, we have given this work to one authority which has to do many other jobs like development of roads, etc. We can experiment it in Delhi. We can appoint a committee and give the function of beautification to that committee. We should also develop parks so that people may have fresh air.

श्री राम विश्व (भरतपुर) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवास और सञ्चार विभाग की चीजों का समर्थन करता हूँ। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो आवास की समस्या है वह बहुत ही कठिन है, और कठिन इस धाने में है कि जिस अनुपात से आबादी बढ़ रही है उस अनुपात से आवास के विभाग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसी प्रकार से इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएँ। अगर सरकारी प्रयत्नों से इस काम को पूरा करने की कोशिश की, जो करनी ही चाहिये, तो भी यह काम केवल सरकार के बजट पर नहीं हो सकता है। हमें ऐसे तरीके खोजना होंगे जिन्हें बाब और महार, क्योंकि आज यह समस्या केवल महारों की ही नहीं रह गई है, आज से पहले यह समस्या केवल महारों की ही समस्या

समझी जाती थी, लेकिन घाज गांव में भी यह समस्या अटिल है और वह इसलिये अटिल है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि उनके पास कोई पैत्रिक जमीन नहीं थी। अब यह गांव बसाये गये थे उस समय जिनके पास जितनी जमीन थी उतनी ही जमीन घाज भी उन के पास है जब कि आबादी उस परिवार की पांच, छः मुना हो गई है। नतीजा यह होता है कि वह सबसे गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उनको कोई बढ़ने नहीं देता। सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है। और घाज जहाँ 40 आदमियों की जगह थी वहाँ 250, 300 लोग रह रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आस तीर पर हिन्दुस्तान के गांव में हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों की नीचे बसाया गया है जहाँ कि गांव ऊँचे में होता है उस का नतीजा यह होता है अब बाढ़ आती है या और कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सब ने पहले गरीब ही प्रभावित होता है इसके अलावा अगर घाज लग जाये तो और जो बड़ी बातियाँ हैं उनके घर बच सकते हैं लेकिन हरिजनों के मोहल्ले में घाज पहुँच जायेगी तो वह नहीं बच सकते हैं। क्योंकि उनके घर पास पास मिले हुए बने होते हैं और इसलिये उनके बचाव का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय उधर ज्यादा ध्यान दें। सहरो के पास संगठन है वहाँ अखबार है, सहरो के लोग पढ़े लिखे हैं वह अपनी भाषा के बिचे बचाव बाल सकते हैं, सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन शामो में आसतीर पर हरिजन और आदिवासियों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई बहुत मजदूर कदम उठाना चाहिये।

14.00 hrs.

मैं सरकार से यही निवेदन करना कि 20-सूची कार्यक्रम के तहत कांग्रेस

231 L.S.—10

पार्टी ने कुछ सवालों को हाथ में लिया था, लेकिन वह प्रचारात्मक मामला ही था। घाज ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिये जगह नहीं है। उस समय सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि हमने 60 लाख भूखंड ऐसे लोगों को दे दिये हैं जो आबाद के लिये अपने मकान बनायेंगे। लेकिन आप मौके पर जाकर देखें। वास्तविकता को समझें तो उन भूखंडों पर उन लोगों का कब्जा नहीं हुआ है। और वह कब्जा इसलिये नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से जो जमीन उनको दी गई थी वह ऐसी थी। जहाँ पर अलायन थे, जहाँ गांव का पानी भरता था या मरबट था या रास्तों पर जगह दी गई थी। इस तरह से घाज हरिजनों के प्रसंग में जो परेशानी होती है, उसका एक कारण यह भी है कि डिस्प्यूटेड लैंड उनके लिये एलाट कर दी गई। घाज गांव में एक प्रकार का तनाव बना हुआ है कि जो जमीन हरिजनों के रहने के लिये एलाट की गई है वह या तो बड़े लोगों की है या मरबट वगैरह की है और गांव वाले उस पर कब्जे के लिये उनको रोकते हैं। आस तीर पर यह अनता पार्टी के लिये परीक्षा की बात है। यह साधारण होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम अपने मासल कास में गांव के हरिजनों के लिये जमीन आवंटित कर दें जो ऊंचाई पर हो, गांव के पास हो, पोखर वहाँ न हो, तो हम एक बहुत बड़ा काम कर देंगे। अगर वह काम नहीं होता, तो हम ऊपरी तीर पर हरिजनों के लिये बाहे कितनी ही सहानुभूति प्रकट करें, लेकिन वास्तव में हरिजन समाज हमारे नजदीक नहीं आ सकेगा। यह जो लोग हैं, ये ही खती खड़ी करते हैं, सबकों पर कल-कारखाने बनाते हैं, अगर उन लोगों के रहने के लिये भी जगह न हो तो

[श्री राम किशन]

इससे अधिक दयनीय स्थिति किसी भी सरकार के लिये कौनसी हो सकती है। पिछली कांग्रेसी सरकार केवल हरिजनों का नाम लेती रही है लेकिन उनके लिये उसने कुछ नहीं किया। अब जनता पार्टी की बारी है, वह इस सम्बन्ध में कदम उठाये।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब हम गांव में भूखंड हरिजनों के लिये धारित करें तो यह नहीं होना चाहिये कि एक घण्टा जगह पर उनको जगह धलाट करे, उस जगह पर कुछ स्वर्ण लोगों को भी जगह एलाट करनी चाहिये ताकि जात-बिरादरी और छुआछाट उसमें से कम हो। घसल में होता यह है कि धाज भी हम हरिजनों के लिये भस्म जगह बनाते हैं, भस्म होस्टल बनाते हैं, भस्म जमीन धलाट करते हैं इससे तो भस्मवाच की बात बनी ही रहेगी।

मैं खास तौर पर राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से अपने धावास मंत्री और सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह धावास मंत्रियों या मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्स दें कि हरिजनों के लिये भस्म से जगह एलाट नहीं की जायेगी। अगर उनके 10 घर किसी जगह बनाये जाते हैं तो वहाँ सबको, ब्राह्मणों के भी ताज्जीबी तौर पर घर बनाये जाने चाहिये जिससे छूतछाट मिट सके और धावसी सम्बन्ध दुस्त हों।

धाज लोगों का सहरोकरण हो रहा है, गांव से लोग सहरों में धा रहे हैं। जनता पार्टी ने जो गांव के विकास की बात की है इसका धमर 2, 3, 4 साल में होगा। लेकिन अब तक सहर में गांव के लोगों का प्रवाह कम नहीं होगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। गांव से लोग सहरों की तरफ इसलिये धास रहे हैं कि वहाँ पर काम नहीं है और बड़े

किसान गांव में उनका शोषण करते हैं। इसलिये वह सहरों में धाना चाहते हैं। एक तो सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि कहीं कोई सरकारी भकान हो या निजी सेक्टर में भकान हो, उनको ज्यादा भूखंड धारित न करें। उनको दो, तीन मंजिले भकान की इजाजत देनी चाहिये जिससे जमीन कम धिरे। धाज स्थिति यह है कि दिल्ली को देखकर मैं दंग रह जाता हूँ जिसमें हिन्दुस्तान के काफी लोगों को बसाया जा सकता है। बड़े बड़े लान हैं, बड़े-बड़े बाग हैं, विदेशी इमारतें है बैसी ही संस्कृति है। हम दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है, हमें उसकी तरफ देखना चाहिये।

मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि गांव के हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनके पास रहने के लिये जमीन नहीं है, एक कालबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस काम को पूरा करना चाहिये। यह जो सरकारी धाकड़े हैं, जिनमें कहा गया है कि 73 लाख परिवारों को जमीन दे दी गई है, मैं म ननीय सिक्कर बख्त साहब से निवेदन करूंगा कि वह भरतपुर में धायें, हमारे बड़ा प्लाट एलाट हुए हैं, धाय मौके पर जाकर देखें कि कितने परसेंट जगह है जहां पर लोगों को कब्जा नहीं है। क्योंकि वह जमीन ऐसी दी गई थी कि उस पर कब्जा ही ही नहीं सकता। हरिजन उस पर धपना भकान बना ही नहीं सकते थे। गड़बों में और पोखरों में मैं नहीं समझता कि कोई धपना भकान बना सकेगा। वह तो हरिजनों के साथ बड़ाक था। इसलिए मैं धाकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। इन पर ज्यादा प्रामाणिकता से बिचार नहीं करना चाहिए।

धाज जिस तरह की हमारी हालत है उसमें नये बितन प्रे, नये दृष्टिकोण से हमें इस समस्या को लेना चाहिए। धावास के लिए जो सरकारी प्रयत्न किए जा रहे हैं उस में पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 700 करोड़ के करीब धाप ने प्रावधान किया है। लेकिन देश की बिशासता और इस समस्या की

जितना को देखते हुए यह एक बड़ा काम था।
 अब की सात 77-78 में भी सरकार ने जो
 एक रकम रखी थी वह इतनी कम थी कि उस से
 इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था।
 हमें दो दृष्टियों से कोशिश करनी होगी।
 एक तो मकान सस्ते हों और उस के साथ
 साथ जगह भी कम बेंरे। हालांकि धाप का
 रिजल्ट जीरो है, इस में आंच भी कर रहे
 हैं और धाप की तरफ से कहा भी जा रहा
 है कि 15 सौ रुपये में मकान बनाने की जगह
 और 35 सौ रुपये में मकान बनाने की जगह
 धाप ने निर्मित कर ली है लेकिन मैं नहीं समझता
 कि इस का प्रचार कहाँ है और किस को इस
 की जानकारी है। शायद थोड़े बहुत लोगों
 को जो दिल्ली में बैठे हैं, इस की जानकारी
 होगी लेकिन अगर पन्द्रह सौ रुपये में मकान
 बन सकता है और गरीब लोगों के लिए मुफ्त
 में जमीन दी जा सकती है तो शायद इन
 मकानों का निर्माण बहुत तेजी से हो सकता
 है। लेकिन यह सारी धाप की खोज गांवों
 में पहुंचनी चाहिए। राज्य सरकारों के
 माफ़त पंचायत समितियों को इस की जानकारी
 मिलनी चाहिए जिस से लोग इस का फायदा
 उठा सकें। अन्यथा प्रचारारम्भ दृष्टिकोण
 से यह बात महत्वपूर्ण हो सकती है, इस का
 व्यवहार में कोई भय नहीं है।

तो आवास के संबंध में सरकार को एक
 स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बना कर चलना चाहिए।

मुझे एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कहनी है।
 माननीय सिकन्दर बख्त के पास दोनों ही
 महत्वपूर्ण विभाग हैं—एक तो पानी का
 और दूसरा आवास का। अगर मनुष्य की
 कोई जरूरत है तो सब से पहले पानी, भोजन,
 कपड़ा और मकान की जरूरत है। तो
 एक तरह से हिन्दुस्तान की जरूरतों के जो
 दो प्रतीक विभाग हैं वे सिकन्दर बख्त के पास
 हैं। मैं समझता हूँ कि इस मामले की तरफ
 सरकार को बहुत सम्भारता से विचार करना
 चाहिए। आज गांवों की हालत क्या है ?
 सरकार ने शहरों के आँकड़े दिए कि हम ने

इतने शहरों में पानी पहुंचा दिया है, इतने
 गांवों में पानी पहुंचा दिया है। मैं धाप को
 जानकारी देना चाहता हूँ। धाप चले जाइए
 राजस्थान में/राजस्थान में आज भी ऐसे गांव
 हैं जहाँ 32 मील दूर से लोग पानी लाते हैं।
 कोई कल्पना नहीं कर सकता। उन के पास
 रेल नहीं है, मोटर नहीं है। सुबह ऊँट गाड़ी
 चलती है और परिवार के तीन घादमियों
 का काम केवल यही है कि वे कुएं के पास
 जाते हैं, सुबह चल देते हैं और शाम को पानी
 लेकर वापस आते हैं। जिन जगहों में धाप
 ने कहा है कि हम ने नलकूप लगा दिए हैं,
 वे सारे नलकूप बन्द पड़े हुए हैं। उन का
 कोई उपयोग नहीं है। जनता पार्टी की
 सरकार ने वादा किया है कि समस्या ब्रस्त
 जो गांव है और दूसरे जो गांव है उन में
 6-7 साल में पानी पहुंचा देंगे। लेकिन
 यह टागैट धाप का बहुत सम्बा है। मैं यह
 चाहूँगा कि धाप अपने कार्यकाल में और
 कोई काम कर पाएँ या न कर पाएँ लेकिन
 मेहूरबानी कर के यह कर दीजिए कि हिन्दुस्तान
 से कोई गांव ऐसा न रहे जहाँ किसी को पानी
 की बखह से कष्ट हो। धाप कल्पना कीजिए
 32 मील से पानी लाना और राजस्थान की
 औरतों जो तीन तीन मील से घड़े को सिर पर
 रख कर पानी लाती हैं उन के कष्ट का अनुमान
 दिल्ली के अन्दर वातानुकूलित कमरों में बैठने
 वाले नहीं लगा सकते। मैं वर्तमान सरकार
 पर यह दोष नहीं डालता। लेकिन पुरानी
 सरकार ने जितना एयर कंडीशनिंग पर
 और दूसरी सुविधाओं पर पैसा खर्च किया
 है उतना अगर हिन्दुस्तान के गांवों में पानी
 ले जाने के ऊपर खर्च किया होता तो हिन्दु-
 स्तान की तस्वीर आज दूसरी ही होती।

हमारे यहाँ एक दूसरी स्थिति और है।
 राजस्थान एक ऐसा इलाका जहाँ उस राज्य
 की धामदनी में पशु धन का हिस्सा भी 30
 परसेंट है। लेकिन जब मनुष्य को पानी को पानी
 नहीं मिलेगा तो पशु के लिए तो सबाल प्राप्ता
 ही नहीं। राजस्थान सरकार यह मान कर

चलती है कि धरम हमें राजस्थान के हर गांव में पानी देन है तो 600 करोड़ रुपये का प्रावधान चाहिए। धरम धाप जानते हैं कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति किसी भी सूरत में ऐसी नहीं हो सकती कि वह 600 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सके। लेकिन केन्द्रीय सरकार के पास कई ऐसे रास्ते खुले हुए हैं, विदेशों के भी रास्ते खुले हुए हैं और देश के भी रास्ते खुले हुए हैं। धाप ऐसे गांवों को उम में प्राथमिकता दें जहां पशुधर्म और मनुष्य के लिए पीने का पानी नहीं है। धरम हम इस तरह से प्रायरीटी फिक्स करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम कम साधनों से जल्दी विकास कर सकेंगे। लेकिन हमारा दृष्टिकोण तो पश्चिम वाला है, वही पश्चिम की संस्कृति, वही पश्चिम के भवन, वही पश्चिम का भोजन। धाप कहेंगे मैं जो पानी की खपत होती है उस का धन्दाज लगाइए, गांवों की खेती पर जो पानी की खपत होती है वह भी उस के अनुपात में बहुत कम पड़नी है। तो हमें इन सारी बातों को नये संदर्भ में नये ढंग से देखना पड़ेगा। मैं सरकारी धाकड़ों की प्रामाणिकता में ज्यादा इमलिए विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि हम जो मीटर पर देखते हैं वह तस्वीर बिमकुल दूसरी है और सरकारी धाकड़ों की तस्वीर बिमकुल दूसरी है। धाप ने कहा कि हम ने कुएं बना दिए हैं, नलकूप बना दिए हैं। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में 250 नलकूप धाप ने बनाए हैं, माननीय मंत्री जी खुद दौरा करने जायें ता देख लें उन 250 नलकूपों में धायद पांच भी चानू नहीं हैं। धापके हिसाब से समस्या का समाधान हो गया लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। पुरानी कांग्रेसी सरकार का यह तरीका था कि नारा दो, प्रचार दो और वास्तव में कुछ करो या नहीं। लेकिन जनता पार्टी की सरकार को यह करना होगा कि वास्तविकता भी मानी पड़ेगी और प्रचार भी करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आशा है और पानी के सम्बन्ध में

दो बातें कहकर धपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

इसके साथ ही राजधानी के विकास के लिए एक विकास क्षेत्र बनाना गया है उसमें कुछ इलाके उत्तर प्रदेश के लिए गए हैं, मेरठ बगैरह को लिया गया है, पानीपत और धरमधर को भी लिया गया है। लेकिन धाप देखें कि दिल्ली का विकास किधर हो रहा है। दिल्ली का विकास मथुरा की तरफ हो रहा है। उधर कारखाने खुल रहे हैं। इससे मथुरा और दिल्ली नजदीक धाने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में धाप भरतपुर को भी शामिल करें क्योंकि वहां पर मीटर-गेज भी है और बाड़मेर भी है तथा दूसरी सुविधाएँ भी हैं। वहां पर तेल का कारखाना भी खुल रहा है। राजधानी के विकास में दिल्ली का जिधर रुकान है उसे धापको देखना चाहिए। सारी स्थितियों को धापको दोबारा देखना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से वे इस सारे मामले को दोबारा देखें। धरम विकास की दृष्टि से कुछ ऐसे इलाके धा सकते हैं जिनसे ज्यादा लाभ हो सकता है, जिनके विकास से ज्यादा धाबादी बढ़ सकती है तो उस दृष्टि से देखने की धरमधय कृपा करें।

एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार ने जान बूझ कर सरकारी क्षेत्र की बदनामी की थी। उनमें धरमधयस्था पैदा करके धाटा दिया था। धापके पास भी सरकारी क्षेत्र के कुछ काम हैं जिनकी रिपोर्ट देखने से पता चलता है। उनमें भी धाटा हो रहा है। किसी में 32 लाख तो किसी में 37 लाख धाटा हो रहा है। इसकी धोर भी धापको धरमधय तह से ध्यान देना चाहिए। धी निर्माणाधीन काम हैं उनको धरम धाप ठीक से नहीं देखेंगे तो स्थिति दूसरी हो जायेगी।

इसी के साथ साथ मुझे निवेदन करना है कि राज्य सरकारों के विकास लिए जो जमीन अधिग्रहीत की है, यदि धाप धांकड़े देखें तो उस भूमि के 50 प्रतिशत का भी विकास नहीं हुआ है। जो शहरों के मुनाफाखोर हैं वे जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकारों ने जिस जमीन का अधिग्रहण कर लिया है उसका एकदम से विकास कर ही देना चाहिए।

एक बात जिसकी मैं विशेष तौर पर चर्चा करना चाहूँगा वह यह है कि जो नगर भूमि अधिनियम था उसमें कोई संशोधन करने की भायद चर्चा चल रही है। मुझे पता नहीं किम प्रकार का संशोधन धाप लाना चाहते हैं। धाप भ्रमन सीलिंग ऐक्ट में कोई संशोधन करना चाहते हैं। धापने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने मुझाब भेजें। धाजकल जो हवा है वह यह है कि शहरी जमीन पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसमें धाप कोई रिलेक्सेशन, छूट, देना चाहते हैं। यह बात किसी प्रकार भी सम्भव नहीं होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने काफी बेनामी प्लॉट से रखे हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इसलिए धगर इस दिशा में कोई संशोधन करना है तो उससे जमीन कम की जाये, बढ़ाने की बात तो उठती ही नहीं है। धगर धाप इस धाधार पर जमीन देना चाहते हों कि वे ज्यादा मकान बनायेंगे तो यह धापकी बिल्कुल गलतफहमी होगी और इस गलतफहमी में धापको कभी नहीं धाना चाहिए। मैं चाहूँगा सरकार इन समस्याओं पर धच्छी तरह से ध्यान दें।

एक बात और मुझे खास तौर पर कहनी है और वह है पुनर्वास के सम्बन्ध में। मैं सारे देश की चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल से धाने वाले माननीय सदस्यों ने शरणाधियों की काफी चर्चा कर दी है। मैं धपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में देवली में बंगाल के शरणाधी रहते हैं।

धजमेर जेल में ऐसे कुछ लोग मेरे साथ थे। यदि धाप उनके कष्ट और उनकी वेदना को देख लें तो मैं समझता हूँ था तो धाप उसको दुबस्त करने के लिए तैयार हो जायेंगे या फिर गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। दोनों में से एक काम धापको करना पड़ेगा। मुझे ताज्जुब तब होता है जब मैं देखता हूँ कि धाप धाज तक राजस्थान में बसे हुए मेवाँ के धावास और रिटैबिलिटेसन का कोई समाधान नहीं कर पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या एक दूसरे टाइप की है। जब भरतपुर और धलवर में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए, उस समय हमारे यहाँ के मेब लॉग पाकिस्तान नहीं गये, बल्कि धपने रिभेदारों के यहाँ गुड़ गांव क्षेत्र में धा गये थे। जब शान्ति स्थापित हो गई और गांधी मिशन की तरफ से हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उन से यह वायदा किया कि धाप वहाँ चल कर रहें, धाप की जमीन, धाप के मकान धाप को वापस मिल जायेंगे, तब वे लॉग यहाँ ध्राये। उस समय तक, उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान के शरणार्थी भी वहाँ धा गये थे और मेवाँ की जमीनें उन को एलाट हो गई थी। जो एलाटेन्ट हो गई, उस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो हो गया सो ठीक है, लेकिन जब मेब लोग वापस ध्राये तो जिन की जमीनें ली गई थीं, उन को भी सरकार ने जमीन एलाट की और वहाँ बसाया गया। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी कठिनाई यह है कि बदले में जो जमीनें सरकार द्वारा उन को एलाट की गई, धाज भी उन का। हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुधाबजा लिया जा रहा है—यह रकम वे लोग कहाँ से लें? खास कर हमारे यहाँ कामा-तहसील में, जो धाज भी बाढ़ से प्रभावित है, धाज भी उस के 17 गांव पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ बदले की जमीन दी जाय और उस जमीन वा पैसा धमूल किया जाय—यह बहुत धन्यायपूर्ण काम है—इस तरफ धाप को तुरन्त ध्यान देना चाहिये। मुझे यह भी निवेदन करना है कि पाकिस्तान से ध्राये हुए शरणाधियों

[श्री रम किशन]

के म मले भी धर्मों तक पूरी तरह से नहीं निबटे हैं। मैं धकड़ों के जंजान को छोड़ कर साफ शब्दों में तीन बातें ध्राप के सामने रखना चाहता हूँ—ध्राप गांव में भूमिहीन हरिजनों के लिये जमीन देने का धान्दोलन चलाइये। राजस्थान सरकार पर दबाव डालिये कि जो जमीन बाड़ से प्रभावित न हो, उन्को जमीन हो, उसे हरिजनों को दिया जाय। शरणार्थियों की समस्या का समाधान किया जाय और पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। ध्राप का कहना है कि 40 हजार गावों को पीने का पानी दे पाये हैं—यह निर्णय ध्राप का कहना है, वास्तविकता नहीं है। राजस्थान में ध्राप चाहे रोटी न दे सकें, रोड़गार न दे सकें, मकान न दे सकें—लेकिन पीने का पानी तो सब से प्राथमिक जरूरत है—उम का इन्तजाम भी घ्र से भी घ्र करें। कांग्रेस सरकार 30 सालों में नहीं कर सकी, लेकिन जनता सरकार को निश्चित तौर पर यह वायदा करना चाहिये कि वह इस काम को तीन सालों में पूरा करेगी। ध्राप को चाहे किसी भी मद में कटौती करनी पड़े, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था सब से पहले करनी चाहिये।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और धूनवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किशनकर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से ध्राप तक 8 माननीय सदस्यों ने मेरे मंत्रालय की बजट प्रनुदानों पर प्रपने विचार व्यक्त किये हैं। उन में से अधिकांश माननीय सदस्यों ने हमारी प्रनुदानों का समर्थन किया है और प्रच्छे मुआव भी दिये हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का भी बहुत धाभारी हूँ जो सदन में उपस्थित रह कर हमारे धनुदानों का मौन समर्थन कर रहे हैं।

मान्यवर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पड़ोसी राज्य

नेपाल में भी इण्डिया-कोआपरेशन मिशन के धनुतर्गत राज-मार्ग परियोजना का भी संचालन करता है। हमारा एक डिवीजन सिविकल में भी काम कर रहा है। 1975-76 में इस विभाग को 70 करोड़ रुपया, 1976-77 में 90 करोड़ रुपया और 1977-78 में 120 करोड़ रुपया काम करने के लिये दिया गया था। और 1978-79 में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस धनुराजि के तहत हमने जो कार्यक्रम 1978-79 के लिये बनाया है, उम में हम लगभग 22 हजार मकान बनायेंगे और वे मकान केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये होंगे। इन मकानों में टाइप 1, 2 तथा 3 के मकान होंगे जो द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये होंगे। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जो मकान बनाये जाते हैं उन में बहुत से प्रथम श्रेणी के कर्मचारी भी रहते हैं। इस प्रकार दिल्ली में 16 हजार मकान बनाये जायेंगे, बम्बई में 2600, कलकत्ता में 2000, हैदराबाद में 500, मद्रास, चण्डीगढ़ और बंगलौर में 300-300 मकान बनाये जायेंगे। ये 22 हजार मकान तीन वर्षों के धनुदर बन जायेंगे। जहाँ तक टाइप एक दो और तीन के मकानों का सम्बन्ध है जो इस वक्त हमारे पास हैं उन में से टाइप 3, 31 प्रतिशत लोगों के पास है, टाइप दो 43.3 प्रतिशत और टाइप 1, 49.5 प्रतिशत लोगों के पास हैं। लेकिन जब तीनों टाइप के ये नये मकान बन जायेंगे तो लगभग 60 प्रतिशत लोगों की सन्तुष्टि हो जायगी।

धाबादी को देखते हुए, सामान की महंगाई को देखते हुए और भवन निर्माण की बीजों की कीमतों को देखते हुए जनता सरकार ने निश्चय किया है कि नया जो प्लान एरिया होगा इन तीनों टाइप के मकानों का उरु में कुछ डिवियेशन किया गया है ताकि ज्यादा संख्या में मकान बन सकें और ज्यादा लोगों को मकान दिये जा सकें।

इसलिए टाइप 1 का प्लिंक एरिया जो पहले 365 वर्ग फीट था अब 300 वर्ग फीट होगा, टाइप 2 का 480 था, अब 350 होगा और टाइप 3 का 600 था और अब 425 होगा। इससे ज्यादा लोगों को एकमोडेन किया जा सकेगा। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए रहने के लिए रिहायशी मकानों को मैंने चर्चा की है।

अब मैं गवर्नमेंट आफिस एक्स.डिशन की चर्चा करना चाहता हूँ, विभिन्न स्थानों पर जो डिमांड है पहले मैं वह आपकी धतलाना चाहता हूँ :

दिल्ली में 75.33 लाख वर्ग फीट
बम्बई में 11.45 लाख वर्ग फीट
कनकला में 24.85 लाख वर्ग फीट
नागपुर में 3.27 लाख वर्ग फीट
गिमला में 2.53 लाख वर्ग फीट
फरोदाबाद में 1.64 लाख वर्ग फीट
मद्रास में 11.12 लाख वर्ग फीट
बंगलौर में 6.67 लाख वर्ग फीट।

इस प्रकार से गवर्नमेंट आफिस एकमोडेसन की कुल डिमांड 137 लाख वर्ग फीट की है। हमारे पास जो अखिल इन्डिया है उसका टोटल 80.43 लाख वर्ग फीट है और जो टेम्पोरेरी हटमेंटस हैं वे 14.01 वर्ग फीट में हैं। इस प्रकार से कुल शार्टेज 59.43 लाख वर्ग फीट की है। अभी निर्माणाधीन स्थान 9.92 लाख वर्ग फीट है और जो बनाने के लिए प्रस्तावित है वह 15.5 लाख वर्ग फीट है। इस में हटमेंटस भी शामिल हैं। निर्माणाधीन 9.92 लाख वर्ग फीट 20 वर्ष में कम्पलीट हो जाएगा। लेकिन 15.5 लाख वर्ग फीट प्रथम तीन वर्ग में ही पूरा हो जाएगा। फिर भी यह नहीं है कि सारी समस्या हल हो जाएगी, जितनी संख्या में लोग सरकारी नौकरी में हैं और जितनी आवश्यकता है उसकी देखते हुए हमने यह प्रयास किया है और साथ ही साथ तेजी से काम भी किया जा रहा है।

जहाँ पर हमारे पास कार्यालय स्थान नहीं है वही पर हम निर्माण को प्राथमिकता देते हैं हमें एग्जिस्टिंग मकान मालिकों को बहुत ज्यादा रुपया देना पड़ता है तब तक उसकी बचत हो सके। अगर हमारे कार्यालय और मकान बन जाएं तो आम जनता को भी उससे फायदा होगा।

केन्द्रीय निर्माण विभाग में एक सैल्फ कंसल्टेंसी कमेटी है जो पब्लिक ग्रैंडरटेकिंग एवं लोक बाटोइ को मकान प्रशासनिक या औद्योगिक भवन बनाने में और उनका क्या साइज होना चाहिये, क्या डिजाइन होना चाहिये, एनविरनमेंट क्या होना चाहिये, आदि राय मशिवरा देती है। इस कंसल्टेंसी कमेटी के बीस करोड़ रुपये से अधिक के मामले हैं जहाँ कि निर्माण कार्य केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ही काम सौंपा जाता है। वहाँ निर्माण कार्य के करने के लिये उपयुक्त स्तरों पर अलग से परियोजना प्रबन्धक टीम का गठन किया जाता है। जो लोग मकान बनवाते हैं, (क्लाइंट्स प्रायोनैडिजेशन) उन्हें राय मशिवरा देकरके उनकी संतुष्टि के अनुसार निर्माण कार्य होता है। लोक निर्माण विभाग ने हिन्दुस्तान पेपर कोरपोरेशन, मैकोन, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और कुदरेमुख लौह अयस्क प्राधिकरण आदि कुछ संगठनों को अब तक की राय मशिवरा दिया है।

विभाग ने हाल में जो प्लिन्य एरिया कम किया और जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं, उससे कम कीमत में ज्यादा मकान बनाये जा सकेंगे। अभी हाल में हमने एक और चीज की है, एक मैनेजमेंट इनफ्रैस्ट्रक्चर सिस्टम का भी गठन किया है जो हमारे मंत्रालय को समय-समय पर रिपोर्ट देता रहेगा कि कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है, क्या दिक्कतें हैं। यह एक नई चीज की है। इनकवायरी आफिसेज में भी हमने प्रयास किया है कि जो स्थानीय लोगों की शिकायतें होती हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाय।

[श्री राम किकर]

जैसे ही जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में बनी हमने कुछ म्योर्टस परचेजस तथा इकाटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की परचेज पौलिसी में बहुत परिवर्तन किया है। हमने काफी बढलाव किया है और प्राइम लाइन को ठीक रखने में और अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये हमने भी तरह तरह की सहूलियतें दी हैं और उनको सहायता भी दे रहे हैं, मशिवरा भी दिये हैं। इस वर्ष मूल्य स्थिर रखने में और सरकार की मूल्य नीति को कायम रखने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये हमारे पूंति विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, और इस विभाग ने ठेकेदारों से बातचीत कर के उनमें भाव ठाव करके और समय-समय पर उनको सहूलियतें दे कर हमने सामान कम वैसे में खरीदा है और इस तरह हमने ट्यून्स, बी० आई० पाइप, बैटरी, यात्रायुक्त के वाहन, बेसिस, कागज और रबड़ की वस्तुओं का बातचीत करके कम दाम में खरीदा है और कभी कभी फिसकल लेवीज के बावजूद दाम नहीं बढ़ाने दिए। परिणामतः 1977 के 8 महीनों के अन्दर ही हमने 5 करोड़ ६० कीमतों में कम कराये है।

बाजार भाव पर लगातार निगरानी रखने और समझ बूझ की वजह से हमने जूट और कपड़ा भी कम कीमत में खरीदा है बावजूद इसके कि कीमत उसकी ज्यादा थी, क्योंकि हमने समय पर देखा कि किस वस्तु कौन सी चीज सस्ती थी। इसलिए हमने उसमें भी बचत की है। हमने स्वदेशी उद्योगों, इंडीजिनस इंडस्ट्रीज, के विकास में भी मदद की है और जो सामान बाहर से मंगाने से अब हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनके सक्टीयूजन में अगर कोई सामान तैयार किया जा सकता है तो हम उन इंडस्ट्रीज को उन प्रोड्यूसर्स को मदद कर रहे हैं। बड़े उद्योग धंधों के मुकाबले में छोटे उद्योग करने वालों को हम भी 15 प्रतिशत प्राइस प्रीफरेंस दे रहे हैं। यहां हमारे सेंट्रल पर्चोइजिंग आर्गनाइजेशन का उद्देश्य है। हमारा सप्लाई

विभाग टैकिंगल डैवलपमेंट डायरेक्ट्रेट के सहयोग से इंडस्ट्रीज को सहायता और राय मशिवरा देकर स्वदेशी पूंति के साधनों के विकास में मदद करता है। इसी कारण हैबी इयूटी, वैड टाहप मिल्डिंग मशीन के लिये हिन्दुस्तान इयूटी मशीन टून्स को ठेका दिया जा सका।

मिट्टी हटाने और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के अलावा 500 घाइटमों के लिये स्वदेशी साधनों का विकास किया गया है। लाइट हाउस इक्विपमन्ट शिपिंगटून्स का भी स्वदेश में विकास किया गया है। मैग्नेटिक टेपों को विकास प्रायुक्त, लघु उद्योग के सहयोग से विकसित किया जा सकता है।

सरकार की इस पर्चोइजिंग पोलिसिसे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा मिला है और उनसे हम काफी सामान खरीद रहे हैं। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की जो 241 घाइटमें हैं वह हम उनसे खरीदते हैं और समय-समय पर प्रोत्साहित करते हैं, सूलियतें देते हैं और जहां परचेज करने और सन्नाई करने के नियमों कायदे-कानूनों में कोई बाधा प्राती है, तो उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। लघु उद्योग में इस वर्ष जो उत्पादन मूलक कम किया गया है उससे 24 हजार यूनिट्स फायदा होगा, और उनमें एक कंपीटीटिव सिस्ट पैदा होगी और हम सस्ते में सामान खरीद सकेंगे।

हमने एक और सहूलियत दी है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निषम में अब तक जितनी इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रीज करा चुकी है, उनको हम प्राटोमेटिक डी० सी० एस० एंड डी० में पंजीकृत मान लेंगे।

आवी ग्रामोघोष प्रायोग से हमने 40 घाइटमों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अनुसोध किया है। 1975-76 में हम ने उनसे 2 करोड़ रुपये का सामान खरीदा था और 1976-77 में 4 करोड़ रुपये का सामान खरीदा।

हमने पूर्ण मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई-पावर कमेटी बनाई थी जिसने यह प्रघिकृत किया है कि कुछ कार्यकारी दल सस्तुतियों का अध्ययन करे और उसके बाद जहाँ कोई दिक्कतें घाती हों उनको दूर किया जाय। इस दिशा में माननीय मंत्री जी की हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू भी हो गई हैं।

इसके प्रतिरिक्त डाक-घार, रेलवे और रक्षा विभाग में भी अध्ययन दल गठित किये गये हैं और उनको कहा गया है कि जो सामान खरीदने वाला है, और जो सप्साई करने वाले हैं, उनकी दिक्कतों को जल्द सुलझाये जाय ताकि देरी न हो और किसी को कठिनाई न हो।

पिछले 20 वर्षों से विशेषकर रक्षा विभाग का बहुत सा सामान डिस्पोजल के लिए पड़ा रहा और उसमें बड़ी कठिनाई होती थी। एक स्पेशल सरप्लस डिस्पोजल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने एक साल में ही लगभग 68 करोड़ 64 लाख रुपये अंकित मूल्य की वस्तुओं का निपटान कर 6 करोड़ 33 लाख रुपये प्राप्त किये और अब 15 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपये का समान बिकने की बाकी है। जो सामान लड़ाई घाटि में बेकार हो जाता है या अन्य विभागों का बिकी का सामान हमारे यहाँ डिस्पोजल किया जाता है।

श्री मीने जिन बातों की चर्चा की है, उनके प्रतिरिक्त अन्य बातों पर मेरे बरिण्ड सहयोगी, श्री सिकन्दर बख्त विचार प्रकट करेंगे। आशा है माननीय सदस्य धैर्य से उन की बातों को सुनेंगे।

*SHRI P. S. RAMALINGAM (Nilgiris): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of my party, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of

Works, Housing, Rehabilitation and Supply.

Sir, none of us can dispute that food, clothing and housing are the basic necessities of human beings and naturally they form the seed-bed for the cultural growth of human society. It cannot also be denied that all the economic activities centre round these three primary requirements. In 1948 the population of Delhi was just 3 lakhs and today in 1978 it is 60 lakhs. According to one survey, only 5 lakh habitations are there in the capital city. There is no wonder that 15 lakhs of people are living in slums. In the metropolitan cities of Calcutta and Bombay the slum-dwellers number about 1 crore. The Slum Clearance Board of Tamil Nadu has achieved the goal of rehabilitating all the slum-dwellers in clean and healthy surroundings, which has proved to be as elusive as an elixir in other metropolitan cities. In this background, especially when it is common knowledge that our entire rural areas are big slums, even the provision of Rs. 1800 crores for housing in the Sixth Five Year Plan is just a flea-bite.

According to a survey conducted by the National Buildings Organisation, at the beginning of the Fifth Five Year Plan the minimum requirement of housing was 38 lakh houses in urban areas and 118 houses in rural areas. Here, it is pertinent to point out that our Finance Minister, Shri H. M. Patel, in his Budget speech has stated that 24 crores of people in our country get an income of 25 paise per day individually. I need not elaborate that with this pittance they will be living only in pits and hovels. The statistics of N.B.O., a Central Government's organisation, have been belied by the figures of our Finance Minister. This N.B.O. has claimed a discovery of cheap house in Rs. 1500 only. Such a house was an exhibit in the Agri-Expo held in November 1977. This should not be mere show-piece. The building

[Shri P. S. Ramalingam]

materials required for such houses and also the know-how must be taken to the rural areas so that our brethren there can save themselves from sun and showers. In 1977-78 Budget Estimate a sum of Rs. 8 lakhs was provided for the rural wing of the N.B.O. and in the Revised Estimate this was reduced to Rs. 6.5 lakhs. I am unable to appreciate this scant regard for rural requirements.

There is imperative need for setting up a Rural Housing Development Corporation, just like the Rural Electrification Corporation, to finance the housing schemes in rural areas. I would like to point out that house-building activities will generate employment opportunities in the country. Sir, in the capital city sky-rise buildings have come up and yet the people who have constructed them are living with sky as their roof and that too 5, 10 miles away from their places of work. It may not be out of place to mention that the Underground Shopping Centre in Connaught Place has generated more rumours of malpractices than trade opportunities. This must be looked into by the hon. Minister.

Sir, the Cement Units and other industrial units producing building materials in the private sector are minting money. It is a paradox that a public sector unit, the Hindustan Housing Factory producing building materials is running under a loss. The argument advanced is that 50 per cent of the installed capacity is not being utilised on account of paucity of orders. When there is acute shortage of building materials in the country, can you accept the plea that there is paucity of orders for the Hindustan Housing Factory? This is far-fetched and seems to be the greatest wonder of the 20th century. I demand that the Public Undertakings Committee of this House should be directed to inquire into the working of Hindustan Housing Factory, in view of the fact that Rs. 2 crores of public money have been invested in this.

The Housing and Urban Development Corporation has sanctioned a loan of Rs. 35 crores to 119 housing schemes of Tamil Nadu. In India, Tamil Nadu occupies premier place in successfully implementing the housing schemes. The HUDCO has released only Rs. 18.18 crores and I request that the HUDCO must be directed to release the remaining Rs. 16.82 crores without delay. Similarly, the HUDCO has sanctioned Rs. 17.37 lakhs for housing projects in Pondicherry. So far only Rs. 40,000 have been sanctioned. This should also be looked into by the hon. Minister. Sir, I will not be boasting in vain if I say that a World Bank Team has applauded the Slum Clearance Schemes Tamil Nadu and it will be worthwhile for other States to emulate them in the interest of resolving the rigours of slum-dwellers.

Out of 3119 towns in our country, only 1890 towns have got pure drinking water arrangement and the remaining 1229 towns have no arrangement for pure drinking water. 217 towns have got underground drainage systems and the remaining 2902 towns have open drains which pollute the entire country. Out of 5 lakh villages in our country in four lakhs of villages we do not have facility for supplying pure drinking water. The Janata Government swears that its source of existence is the growth of rural areas. In fact, its life-breath is claimed to be rural development. Yet a sum of Rs. 40 crores was allocated for rural drinking water in the Budget Estimates of 1977-78 and in the Revised Estimate it has been brought down to Rs. 38 crores. Sir, it should not be forgotten that the food requirements of 60 crores of people are met by the rural residents and if their basic requirements like pure drinking water and a dwelling place are not met by us, we will be committing the gravest injustice to them.

Sir, kindly see the influx of repatriates from Burma and Sri Lanka. 8,71,685 people who have come from Sri Lanka have got Indian citizenship. 2,70,261

of them have been rehabilitated and 95,424 are yet to be repatriated. In 1978 their inflow is going to be 20,000 families. By 1981, according to Shastri-Sirimavo Agreement, we have to take back 3 lakhs of more people. From Burma already, 70 2,07,000 people have already come. They had originally gone from Tamil Nadu and most of them are plantation labour. In my constituency, in Nilgiris, the Tamil Nadu Government has rehabilitated many of them by setting up plantations. 45 schemes of rehabilitation are under various stages of implementation. As if this burden is not enough, we have also to bear the brunt of refugees from Viet Nam. The Refugee Rehabilitation Corporation is short of funds for assisting the State of Tamil Nadu in the matter of rehabilitation programmes. If the Central Government does not come forward to exhibit their munificence, the economy of Tamil Nadu will be in shambles. The statistics of refugees as indicated in the Annual Report of the Department of Rehabilitation for 1977-78 reveal that Tamil Nadu has given succour to most of the uprooters from Sri Lanka, Burma and Viet Nam. The repatriates who will pour in till 1981 from Sri Lanka will also have to be given protection by Tamil Nadu. I appeal to the Government that the massive rehabilitation assistance to be given by the Central Government to Tamil Nadu should not in any case be treated as Advance Plan Assistance; it must be outright grants so that the State of Tamil Nadu is able to garner all its energies in the rehabilitation programmes.

Thanking you for giving me an opportunity to participate in this important discussion, I conclude my speech.

श्री एम्बेजी लाल यादव (धनवर):
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धनिक समय लेना नहीं चाहूंगा। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के दो जिले—धनवर और भरतपुर—एसे हैं जहाँ रिहैबिलिटेशन की बहुत पुरानी

समस्या चल रही है। जैसा कि मेरे साथी श्री राम किशन जी ने बताया, कुछ मेव गुडगांव में, कुछ दिल्ली में और कुछ दूसरी जगह चले गए थे। थोड़े दिन बाद ही वे वापिस भी आ गए थे लेकिन बूक रिकार्ड में उनको एक दफा गया हुआ दिखा दिया गया था, उनको अपनी असली जमीन नहीं मिल सकी। सरकार ने उनको दूसरी जमीन दे दी। एक तो उनके साथ अन्याय यह हुआ कि जो अपने खेत छोड़ कर गए थे वह उनको नहीं मिले। उनको दूसरी जमीन मिली। उसके बाद अब सरकार मुद्दाबड़े के तौर पर उनसे एक हजार रुपया की एकड़ के हिसाब से वसूल करना चाहती है। व बेकारे गरीब किसान हैं। वे इतना रुपया मोहैया नहीं कर सकते हैं। येनकेनप्रकारेण वे इस बात को एबायड करते रहे लेकिन अब सरकार काफी सख्ती कर रही हैं। इसलिए मैं मौजूदा जनता सरकार से चाहूंगा कि जो एक हजार रुपया एकड़ लेने की बात है उसको माफ किया जाये।

इसी मिलसिले में एक दूसरी समस्या भी है। कुछ कास्तकार एमे थे जो मुसलमानों की जमीने कास्त करते थे। मुसलमान बूक चले गए उनकी जमीने हिन्दू या मुसलमान कास्तकारों के कब्जे में रह गईं। उसके बाद राजस्थान में जो टैनीसी ला बना उसके तहत वह जमीन उन कास्तकारों के पास ही रह गई लेकिन सरकार ने यह तय किया कि इस जमीन से उनको बेवखल न किया जाये पर मुद्दाबड़े के तौर पर उनसे कम्पेसशन जरूर वसूल किया जाये। इस मिलसिले में मैं भर्ज चाहूंगा कि एक कास्तकार राम की जमीन कास्त करता था और दूसरा कास्तकार रहीम की जमीन कास्त करता था लेकिन राम की जमीन कास्त करने वाला अब तक मुफ्त में कास्त कर रहा है और रहीम की जमीन कास्त करने वाला जो है, उसको, बूक रहीम—मुसलमान था और पाकिस्तान चला गया, एक हजार रुपया की एकड़ मुद्दाबड़ा देना पड़या। यह समस्या हमारे धनवर और

[श्री रामजी लाल यादव]

भरतपुर, दोनों जिलों की है। संवत् 2003 में जो काश्तकार मुसलमान की जमीन पर बैठे थे और धाज तक बैठे हैं उनसे केवल इस कारण मुद्दा खड़ा बमूल करना कि वे मुसलमान की जमीन काश्त करते थे, मैं समझता हूँ यह डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब राम की जमीन को काश्त करने वाले से मुद्दा खड़ा नहीं लिया जाता तो रहीम की जमीन को काश्त करने वाले से क्यों मुद्दा खड़ा लिया जाये ?

तीसरी समस्या यह है कि जो लोग पंजाब सिद्ध से घाये थे उनको झलवर और भरतपुर में बसाया गया, उनको कुछ घांट दी गई और कुछ लोन के तरीके पर दिया गया ताकि वे रिहैबिलिटेड हो जायें। वे लोग इतनी गरीबी और खस्ता हालत में घाये थे और उनके रहने का तौर तरीका भी धन्य था कि उस थोड़े से पैसे से वे धाज तक अपने धापको धच्छी तरह से बसा नहीं सके। नतीजा यह हुआ कि जो लोन उन्होंने लिया था रिहैबिलिटेसन के लिए वह लम्बे धर्से से वाकी बला धा रहा है। एक बार झलवर और भरतपुर में इसको लेकर धान्दोलन हुआ था कि हमारा जो कर्जा था उसको माफ किया जाये। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं और लोग जेलों में भी गए थे लेकिन धभी तक उस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। इसलिए मैं धापके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो लोग धभी तक उस कर्ज को धदा नहीं कर पाये उनका कर्जा माफ किया जाये। धभार सरकार की स्थिति यह हो कि वह कर्जा माफ न कर सके तो कम से कम बे ब्याज उनसे बमूल किया जा रहा है उसको माफ कर दिया जाये। उनको कर्ज में जितनी रकम मिली थी उससे कई गुना ज्यादा ब्याज की रकम हो चुकी है।

चौथी बात जो मैं धर्ष करूंगा, वह यह है कि राजस्थान, जैसा मेरे साथी श्री रामकिशन

ने बतलाया, ऐसा प्रदेश है, जिस में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पर कांग्रेस के तीस साल के शासन ने कोई गौर नहीं किया। राजस्थान के खेत प्यासे हैं, राजस्थान का किसान प्यासा है, राजस्थान के मवेशी प्यासे हैं। इसी उन्मीय है कि धाने वाली जनता सरकार राजस्थान की जनता को पानी दे सकेगी, उन्होंने जनता पार्टी के 24 एमपीज यहाँ चुन कर भेजे हैं। राजस्थान नहर का मामला बहुत पुराना पड़ा हुआ है, वह एक धलन विषय है, लेकिन जहाँ तक पीने के पानी की समस्या है, धाप की तरफ से ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर इस काम को पूरा कराया जाना चाहिये, क्योंकि हमारा राजस्थान इनना गरीब राज्य है, जिसके पास क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन धामदनी के जरिये की दृष्टि से—वहाँ धामदनी के जरिये बहुत ज्यादा नहीं है। इस लिये मैं माननीय मंत्री जी से धार्थना करूंगा कि राजस्थान में पीने के पानी की दृष्टि से ज्यादा ब्यवस्था की जाय।

राजस्थान सरकार और धापकी सरकार जब नकसा बनाने बैठती है तो कहती है कि हम दो हबार से ज्यादा की धाबादी वाले गांवों में पीने के पानी की ब्यवस्था करेंगे जहाँ तीन हबार से ज्यादा धाबादी है वहाँ पीने के पानी की ब्यवस्था करेंगे लेकिन जो गांव छोटे हैं जिनको बहुत दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है—उनके लिये क्या ब्यवस्था होगी इस तरह से तो उन बेचारों को कभी भी पानी प्राप्त नहीं हो सकेगा। राजस्थान में बहुत छोटे-छोटे गांव हैं। इसलिये मैं धार्थना करूंगा कि ऐसे गांवों का सर्वे कराया जाय और उन गांवों में जहाँ 10-15 मील से पानी लाना पड़ता है चाहे उनकी धाबादी 100 की भी हो उनमें जल्द से जल्द पानी की ब्यवस्था की जाय।

इन जर्दों के साथ मैं धाप को धन्यवाद देता हूँ।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Mr. Deputy-Speaker, Sir, of all the functions of Works and Housing, provision of better Housing is most important and there are serious problems in providing better housing facilities. You will be surprised to know that for provision of housing facilities there is a Corporation called Housing and Urban Development Corporation, that is, HUDCO. The performance of HUDCO is very very unsatisfactory. I am speaking about the residential areas. In Sarojini Nagar area there are many buildings which have been built up for educational institutions, colleges, etc. and these should not be hotel building for dancing and drinking. In Bharat Dwar area and Kalibari Marg area where religious functions are held, sites have been allotted for the purpose of hotel complex, theatre, etc. This place should not have been utilised for these purposes. Now, there are Housing Boards which are working in some States also, which have been asking for financial assistance. Housing Boards in the States like Kerala, West Bengal, Tamil Nadu, Bihar, Assam, etc. have written so many letters to the HUDCO for help. In spite of their repeated reminders, no assistance was given by the HUDCO. This matter should be looked into by the Minister concerned.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, in regard to water supply and sewerage facilities in villages, practically no moneys has been provided in the budget for this purpose. You will kindly see on page 78 of the report that Rs. 44.63 crores have been provided for housing in urban areas, whereas no amount has been provided for housing in rural areas. There is no proposal for housing the poor, the workmen, the agriculturists, the common people. We always speak for the poor and common people! As a matter of fact in the plan budget it could be seen from pages 76-80 of this book, that no money had been allotted for housing the poor, the workers, the agriculturists and farmers and the villagers—reventy per cent of our people live in the

villages. What do we find in big cities like Calcutta, Madras and Bombay? Big houses, cooperative houses are being built at the cost of the financial institutions, the promoters are making money. I say that money should be used for the welfare of the poor people who have got no houses. I request the hon. Minister to look into the matter. You have a housing factory and that factory had constructed over 6000 houses with corrugated sheets, etc. Out of them 670 or so had fallen down, had collapsed. There is so much waste of money, this should be looked into. You can find it from the records.

Then with regard to the refugee rehabilitation problem, the refugees coming to West Bengal from Dandakaranya are not being settled properly; maintenance is not being given to them. Dandakaranya authorities are doing nothing. There are so many organisations and they look after themselves, not after the welfare of the people living in the Dandakaranya. They have no means to live and that is why they are compelled to leave Dandakaranya and go to West Bengal. With regard to the rehabilitation of people coming from the former East Pakistan, now called Bangla Desh, their cases had been ignored; their cases had not been considered at par with those coming from West Pakistan. As Prof Samar Guha had said, I must say this; it is very unfortunate those people are moving here and they are not getting government assistance for rehabilitation. There are so many places in Andamans and Nicobar islands. Why don't you settle them there. We represented on this matter to the Prime Minister; the Prime Minister gave a patient hearing and he had assured us that he would look into the matter. I should request the Housing and Rehabilitation Minister to look into this matter and see that the refugees coming to West Bengal are resettled in Andamans.

There is mention about Rehabilitation industries Corporation. I want to tell the hon. Minister that out of 19 units under this corporation, eleven are closed. It was correct that over

[Shri D. N. Basu]

5000 workers were working but now 3300 employees have been thrown out of employment as a result of the closure of some units which was because of a dispute between the authorities and the workers. The Chief Minister of West Bengal had written to the Government of India time and again asking for assistance. Without money they cannot implement the programmes. I should request the hon. Minister to see that necessary funds are provided for running that organisation. There are so many unemployed youths throughout the length and breadth of the country. What are you going to do with this Rehabilitation Industries Corporation and other small industries, although the small industries are not under your jurisdiction? The Rehabilitation Industries Corporation is under your jurisdiction and you should see that they are properly employed.

15 hrs.

Then I come to sewerage schemes in the rural area. It is really deplorable. Water does not flow. There is no adequate arrangement. The rural areas, where seventy per cent of the people live, they have not been given importance at all. They should have been given the top most priority. How much money have you provided in the Budget for the upliftment of the rural people? Nothing. The programmes for the improvement of the sewerage have been kept pending. Why is it that the programmes have been held up? Why is it that the programmes have not been implemented? It is all due to Rolling Plan. What I want to tell you, Mr. Deputy Speaker, Sir, is that due to defects in the Plan, it is not being done. This Rolling Plan will not serve the purpose. As I have already mentioned, if you look to page 76-80 of the Budget for 1978-79 you will see what amount has been provided for the upliftment of the rural people. It is nothing.

Then I come to National Highways. I believe that the Minister does not have the fortune of going through the National Highways. He is always flying.

The National Highways are not being properly repaired, they are not being properly maintained, the repair works are not adequately done. I know some construction of Government buildings are going on in Calcutta for years together.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): You are knocking at the doors of the wrong Ministry.

SHRI DHIRENDRA NATH BASU: These are under you. You would be the Head of the department. You should be dynamic. Our Minister should see that the decisions taken by the Government and by the Ministry are properly implemented. There are so many organisations and agencies; but they are not working properly. Who will be responsible for that? Should we hold them responsible or should we tell our Minister? We should tell our Minister. We appeal to our Minister that he should look into it personally and see that the works are properly done. If the projects taken up are not properly implemented, there is no necessity of keeping the schemes in paper, in black and white. The schemes should be implemented in all fairness.

Then I come to the rehabilitation problem. You must consider it as a very important national problem. As a result of partition of the country, the refugees had come from East Bengal or former East Pakistan, now Bangladesh. Even now, daily three to four hundred refugees are coming from Bangladesh. Who will be responsible for the maintenance of those people? The West Bengal Government, a truncated province cannot take charge of the whole thing, unless they are financed by the Centre. The Chief Minister of West Bengal has been writing to you again and again for assistance and for provision of money for various projects for improvement of the refugees. But nothing has been done. The Loans were

W. & H.

granted to refugees in West Bengal, but they are being realised. But in other cases, which I cited, in the case of refugees from West Pakistan, they were given shelter, they were given every thing. Why do not you treat them on par with others? That is our appeal. So, Mr. Deputy Speaker, Sir, I would request you to kindly see, to kindly use your influence as well, over the Ministry, that rehabilitation of refugees is properly done. Thousands of people are coming from Dandakaranya. What for? Some people are there some organisations are there who are purchasing tickets for them and they are sending them back to West Bengal. What are these organisations? You must find them out and the guilty must be punished.

SHRI A. K. SAHA (Vishnupur): You must see who are the persons behind this.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: They must be found out and the guilty must be punished.

Now, the point is that unless they get amenities, unless they get conveyance charges, unless they get maintenance charges, how can they go back? So, I would request through you, Mr. Deputy Speaker, Sir, that the Ministry should look into the matter and see that the persons are well settled and rehabilitated. You can send them to Andamans and resettle them there.

I again come to that point. Article 370 of the Constitution should be deleted. What for? In Jammu and Kashmir there is enough land and you cannot settle anybody? People also may go and settle themselves there.

SHRI SIKANDAR BAKHT: What about Article 370?

SHRI DHIRENDRANATH BASU: People may go there and settle themselves. Article 370 of the Constitution should be deleted. Nobody from outside Jammu and Kashmir will be entitled to build his house there. What

S. & R.

is this? That is part and parcel of the country. That is a State of this big country, India. Why there should such an Article in the Constitution? That should be deleted and that should go. That is what I mean to say.

Finally, I would appeal to the hon. Minister to see that West Bengal gets due share and Justice from the Central Government for rehabilitation, not only for rehabilitation but for improvement of people who have already settled there. This is a national problem. So, the Central Government cannot sit idle over this issue. That is my appeal to you.

श्री राम बिल स पासबन (हाजीपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो, तीन बातों की
झोर मंत्री महोदय का ध्यान आकषित कर ता
चाहूँगा।

पहली बीज मैं उनसे यह जानना चाहता
हूँ कि जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जो
पुराने लोग हैं, जिस पद पर हैं, जो भ्रष्टर हैं
उसमें मे कितने लोगों को अभी तक हटाय
गया है ?

एक घटना की राट मैं मंत्री महोदय को
दिलाना चाहता हूँ। डी०डी०ए० में 18 मई,
1977 को एक घटना घटी थी। 18 अप्रैल
को मैं डी०डी०ए० में गया हुआ था वहां
करीब 12, 14 हजार डी०डी०ए० के
एम्पलायी उस समय थे, वहां जाकर हमने
घाषण दिया था और कहा था कि जनता
पाटों की सरकार जो बनी है, अब घाष
सोगों की मांगों पर हम विचार करेंगे और
मंत्री महोदय से कहेंगे।

18 अप्रैल को डी०डी०ए० के एक
एम्पलाई, कमलकांत चड्ढा, की, जो वहां
जूनियर स्टेनोग्राफर था, किसी दूसरी जगह
सोनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर प्रमोशन
हुई। उसने वहां से रिजाइन किया, लेकिन
उसको रिजोब नहीं किया गया। इस पर वह
एक महीने की छुट्टी पर चला गया। 19 मई
को वह अपने भ्रष्टर के पास गया और

[श्री राम बिलास पासवान]

कहा कि मुझे रिलीज किया जाये, मैंने दूसरी जगह जायन करना है। लेकिन उस भ्रष्टसर—क्रिनासल एडवाइजर, पी० एल० मदान—ने उसे नहीं जाने दिया। धापको यह सुन कर दुख होगा कि जब श्री चहड़ा ने रिक्वेस्ट की कि मेरी पांच बहनें हैं और मेरे परिवार का भरण-पोषण करने वाला और कोई नहीं है, यदि मुझे नहीं जाने दिया जायेगा, तो मेरे परिवार के लोग भूखों मर जायेंगे, तो उसे वह जवाब दिया गया कि तुम भले ही भूखें मर जाओ, लेकिन तुम्हें रिलीज नहीं किया जायेगा। इस पर कमलकांत चहड़ा ने विकास मीनार की 17वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। विकास मीनार उसके लिए बिनाश मीनार हो गया। वह मर गया। मरने से पहले उसने अपनी जेब में एक चिट्ठी लिख छोड़ी कि मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ।

15.11 hrs.

[Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair].

जब मुझे मानूस हुआ, तो मैं दोड़ा दोड़ा दिन के 11, 12 बजे मंत्री महोदय के पास गया। सौभाग्य से मंत्री महोदय वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चिनिये। हम लोग डी०डी०ए० बिल्डिंग गये। वहां मजदूर लोग काफी आक्रोश में थे। मैं मंत्री महोदय की बहादुरी की दाद देता हूँ। वह गये और सेक्रेटरी को बुलवाया। पूछा गया कि पी० एल० मदान कहाँ है। सब एम्प्लोईज ने एक स्वर से कहा कि पी० एल० मदान श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी का चमचा था, वह रिटायर हो गया था, लेकिन उसको पैसा कमाने के लिए डी०डी०ए० में भेज दिया गया, उसे कहा गया कि फ्लैट बनवाओ, उसमें करोड़ों रुपये कमाओ और हमें भी उसमें से शेयर दो।

हमारे जाने के बाद एनक्वायरी हुई। लोगों ने बताया कि पी० एल० मदान यहीं

था। वह हंगामे के डर से लिफ्ट से निकल कर भाग गया है। मंत्री महोदय ने घोषणा की कि जो घटना हुई है, वह बहुत दुखद घटना है, उसके लिए हमें भ्रष्टासोस है, और मैं प्रधान मंत्री के रिलीफ फंड से पांच हजार रुपये दितवाऊंगा। वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे, मंत्री महोदय ने उनसे कहा कि देखो, पी० एल० मदान कहाँ है, उसने फाइम किया है, उस पर मर्डर का मुकदमा चलना है, वह जहाँ कहीं भी है, उसे पकड़ कर कानून के हवाले करो।

धापको सुन कर आश्चर्य होगा कि उसके तीसरे दिन मैंने प्रश्न बाटों में पड़ा कि पुलिस ने अपनी फार्डिंग दी है, अपनी इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट में कहा है कि पी० एल० मदान उस दिन छुट्टी पर था। धाप सभ्य सकते हैं कि भारत सरकार का मंत्री वहाँ मौजूद था, वही डी०डी०ए० बिल्डिंग में एक संसद सदस्य मौजूद था, वहाँ पर श्री कर्पूरी ठाकुर का धापण हुआ, जो अब बिहार के मुख्य मंत्री हैं, सब एम्प्लोईज वहाँ मौजूद थे, और सब लोगों के बीच में कहा गया कि पी० एल० मदान अभी यहाँ था, वह लिफ्ट से नीचे उतर कर कहीं चला गया है। पुलिस अधिकारियों को वह सब बताया गया, लेकिन तीन दिन के बाद समाचारपत्रों में छाता है कि वह छुट्टी पर था। इससे ज्यादा अप्रोफेसी और भ्रष्टासराही का नया नाच क्या हो सकता है? एक गरीब एम्प्लोई का जीवन जाये, मंत्री महोदय और संसद सदस्य के नाचने में सारी बात हो, लेकिन भ्रष्टासराही का इतना नया नाच कि तीन दिन के बाद जनता को बताया जाता है कि वह भ्रष्टासराही छुट्टी पर था।

मैंने एक बार पहले भी कहा था कि चाहे जितनी अच्छी नीतियाँ और अच्छे कानून बनाये जायें, लेकिन अगर उनका कार्यान्वयन करने वाले वही पुराने अप्रोफेस, भ्रष्टासराही और नौकरशाह हैं, तो वे उन

नीतियों और कानूनों को कभी लागू नहीं होने देंगे। इस लिए मैं न सिर्फ़ आवाज मंत्री में, बल्कि भारत सरकार के तमाम मंत्रियों में, आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने पुराने लोग जिस जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर कोई मंत्री घाने के बाद तीन दिन के अंदर आई०ए०एस० धरवा किसी अन्य अधिकारी को नहीं हटाता है, तो फिर उस अधिकारी को हटाना असम्भव हो जाता है। ये अधिकारी एक नम्बर के घूर्ण होते हैं। वे "यस सर" और "नो सर" कह कर, और बिना कहे मंत्री के लिए फल और उनकी बीबी के लिए साड़ी और छोटी ला कर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि उनको हटाना नहीं जा सकता है। तीन दिन में ही उसके बारे में मंत्री का यह विचार बन जायेगा कि वह अफसर बहुत भ्रष्टा है।

इन लोगों की स्थिति अरबी घोड़े के समान है। ज्यों ही कोई बुद्धवार किसी अरबी घोड़े पर चढ़ता है, तो घोड़ा समझ जाता है कि बुद्धवार कितने पानी में है। यदि बुद्धवार नीसिबुवा हुआ, तो घोड़ा उठा कर कहीं पटक देगा और अपने खेत खाने लगेगा। यदि बुद्धवार मजबूत हुआ तो घोड़ा भी अपनी चाल पर चलता है। तो मैं अपने मंत्री महोदय से कहूँगा कि आप ऐसे बुद्धवार बनिए कि जितने ये अरबी घोड़े हैं जो आई०ए०एस० आफिसर और बड़ी-बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए लोग हैं वे सब चुस्त और दुस्त रहें और आपकी नीति का कार्यान्वयन हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ने झुग्गी सोंपड़ी वालों को जमुना पार में बसाया है। मैं वहाँ गया था कल्याणपुर, खिचड़ीपुर, जमीबाबंद। करीब पाँच सात मूहल्लों में गया। हर रविवार के दिन वहाँ निकल जाता हूँ। मैंने यहाँ सबाल भी किया था। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूँ कि आप पार्लियमैटरी कमेटी बना दें या मंत्री

महोदय हमार साथ चलें और देखें, आपको आश्चर्य होगा दिल्ली की इस महानगरी में जहाँ एक से एक बड़ी भट्टालिकायें हैं, वहाँ प्राप गरीब को बसने के लिए जमीन देते हैं लेकिन नहीं सँचते कि उसमें वह किस तरह रहता होगा। 7 गज बाई 3 गज जमीन देते हैं। वहाँ सड़क पर बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। जो पाखाना है न उसको सैपटिक लैंट्रिन कह सकते हैं, न सॉबिस लैंट्रिन कह सकते हैं। अस्पताल है, बारह बजे रात में अगर कोई एमरजेंसी का मामला हो जाये या कोई आफत हो जाये तो कोई देखने खला नहीं है। स्कूल नाम की कोई चीज नहीं है। जो नाला है उसमें गंदा पानी बरा रहता है। उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। न पानी की ही वहाँ व्यवस्था है। आपने गरीब को जमीन दे दी बसने के लिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कल को आपके सामने फिर प्राक्लैम होगा और झुग्गी की बात है दिल्ली का प्राप जितना विस्तार करते जायेंगे इसका कहीं और छोर नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्राप कोई ऐसी नीति निर्धारित करें कि दिल्ली बड़े भी तो कल को उसमें फिर बुलबुलर न बनाना पड़े। फिर यह न कहना पड़े कि यह गन्दी बस्ती शहर के लिए शोभा नहीं देती। दिल्ली को खूबसूरत भी रहना चाहिये। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की योजनाओं में जरा सा प्राप ध्यान दें कि गरीब का भी जीवन है।

अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। संसद् सदस्यों के लिए प्राप फ्लैट देते हैं। मुझे कोई प्रापति नहीं है। लेकिन प्राप फ्लैट उठा कर देखें कि किस संसद् सदस्य को अभी तक प्लाट मिले हैं। क्या कोई गरीब संसद् सदस्य दिल्ली में फ्लैट ले सकता है। 1 हजार रुपये उसका वेतन है। सब काट कूट कर जो बचता है उसी में से प्राप कहते हैं कि मुझे फ्लैट लो। फ्लैट लेंगे तो उसमें जमा कितना करना पड़ेगा—35 हजार। 35 हजार हम चोरी नहीं करेंगे

[श्री राम बिलास पासवान]

तो कहाँ से ला कर देंगे ? वही एम०पी० यहाँ दिल्ली में फ्लैट ले सकता है जो दो नम्बर का कारोबार करता हो या घर का खुसाहास हो। कोई गरीब एम०पी० कभी इस दिल्ली में फ्लैट नहीं ले सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जितने संसद् सदस्य दिल्ली में फ्लैट लिये हैं उनकी क्या इनकम है, उसमें कितने हरिजन हैं, कितने गरीब हैं, कितने घादिवाली हैं। बेरा कहना यह है कि या तो घाप एम०पी० के नाम से फ्लैट मत दीजिए या दीजिए तो जो मन्बली फीस लेते हैं उसको लेकर दीजिए। तभी गरीब एम०पी० यहाँ फ्लैट ले सकेगा। कहना तो बहुत काफ़ी था लेकिन घाप बंदी बजा रहे हैं तो मैं बंद जाता हूँ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE
(Jadavpur): Only two days back, we had a calling attention on the question of exodus from Dandakaranya. Therefore, I do not wish to go to details again. But I would request the hon. Minister to kindly appreciate that on this question politics is being introduced. We have heard the speech of Mr. Saugata Roy. It is unfortunate how they are now trying to utilise the situation in West Bengal to political advantage. It has been decided by the Government of West Bengal, after considering its capacity, the availability of land and all other questions that it is not possible to keep them in West Bengal, whatever may be our intention or desire from heart. It has been appreciated by the hon. Minister here. He has also felt and agreed that it is not possible to resettle them in West Bengal. The hon. Prime Minister has said that they have to be persuaded to go back to Dandakaranya or other places from which they have come. If the matter is being delayed, very serious consequences will follow. Apart from political overtone that is being injected into it, an explosive situation day by day is created. These people have to be looked after so long as they are in

West Bengal. They are taken to refugee camps until they are persuaded to go back to their places. It amounts to huge expenses. Then they are to be given some monetary assistance. Some food articles are to be provided to them. Health and medical care has to be taken. Sanitary problem has to be solved. Now the people are under the sky with no possibility of giving adequate facilities to them. Therefore, my earnest request to the Minister is to see that some assistance is given to the West Bengal Government. Let it be treated on the basis of war footing. We do not want to do anything or say anything which will aggravate the trouble. But my appeal to the hon. Minister is that, this is a national problem, a human problem. Nobody should try to score political victory here. Even a senior Member, Mr. Samar Guha, could not resist the temptation of bringing in politics in a matter like this. We are not going into the post mortem as to why they have come. But the confidence of these people has to be earned. Therefore, my request to the Minister is, please announce that you will give adequate financial assistance to the West Bengal Government and a clear declaration of policy that the Central Government will not encourage such desertion from the camps.

Secondly, about the way how to persuade them to go back, the hon. Minister did not commit himself. Some maintenance grant may be provided to these people. It is necessary to investigate—and I request the Minister to get the central agency to investigate into that—who are the people behind them, who have made bulk purchase of tickets for them, who have made the provision of trucks—Rs. 8000/- a trip—for them. When they are getting down at the railway station, they are being received by interested parties. And there is an attempt to create difficulties as much as possible in trying to divert them to Sunderbans which is already populated. My earnest

appeal to the hon. Minister is kindly declare your intentions very clearly and provide necessary financial assistance.

The Refugee Rehabilitation Committee which has been formed earlier, have given various recommendations. Some of them have already been accepted by the Government. Some of them have not been accepted. But those which have already been accepted, implementation is being held up because adequate fund to the State Government has not been provided. I will request the hon. Minister to kindly look into this matter and make necessary provision for funds.

With regard to Bangladesh refugees who come during 1971, during that time, if I am not mistaken, about Rs. 21 crores are being demanded by the Central Government from the West Bengal Government. This is an old legacy which the present Government has to face with all other difficulties. Therefore, my earnest appeal to the hon. Minister is that he should realise the problems of the State Government and the additional problems which are being accumulated for no fault of theirs and therefore, please do not insist on the realisation of Rs. 21 crores.

There is one aspect of the rehabilitation problem which nobody can deny. I want to make it clear. I do not grudge that if any refugee or any brother or sister of ours who had to come away from the erstwhile Pakistan and had to be settled there, he or she is settled properly. That is what is desirable and necessary. Can it be denied that adequate pecuniary compensation was given to people coming from one sector and such compensation was not given and has not been given to people coming from the other sector? I do not want to create any division amongst those unfortunate people. But this is a fact of history. The people had to come away from both the sectors for no fault of theirs. They have been the victims of a poli-

tical decision for which the responsibility was taken by no less a person than Pandit Jawaharlal Nehru, who openly said that it will be the responsibility of the Government of India and that they will be rehabilitated.

I know, the present Government has got many legacies. This is one legacy which it cannot avoid by merely closing their eyes and saying with a feeling of satisfaction that they have solved the problem of refugee rehabilitation. They have not solved it; they do not solve it. After all, there are human elements involved. Sometimes, because of the uncertainties, interested parties do take advantage and that is being done now. Therefore, to discourage such people from taking advantage and fishing in troubled waters, some sort of a decision is overdue, long long overdue.

It is very easy to say, "I am giving you land which will become fertile in 1982. In the meantime, you will remain in the camp and get some amount of money as daily wages." You cannot involve people in such type of work. You cannot get attachment of the people to such type of life. In such circumstances, it is very easy to divert their attention and even to mislead them. I know, it will be said, it is very difficult to give compensation to those persons. The present policy is that *ex gratia* payments are being made to the people who have left their property in Bangladesh, the erstwhile East Pakistan. Who are getting this money? If you go through the records and the statistics of the persons who have got the money, they are all very rich persons who have left hundreds of acres of land and big properties. But about those people who have left small properties, impossible requisitions are made to them. I know that this Ministry is not directly concerned with it. It is the Commerce Ministry which is the administrative Ministry concerned with that. It is a peculiar system. The problem of rehabilitation is also

there. But the administrative Ministry is the Commerce Ministry so far as the payment of this compensation is concerned. Because the question of rehabilitation is also involved here. I would request the hon. Minister to get in touch with the Commerce Ministry in regard to this matter. The money which is being given as *ex gratia* payment should go to persons who deserve much more than persons who may be able to have preserved their old records to show that they had left properties worth lakhs of rupees.

The other thing is with regard to the Government of India Press. I have been requested the hon. Minister about it to the extent of possibly creating even disgust in him. Once more I appeal to him. The Government has made a good gesture. When Mr. Madhu Dandavate announced the proposal, the decision, of the Government to restore employment to all those who had been retrenched during the Emergency, we applauded that. We are thankful to this Government for that. We appreciated it; that was the spirit which we expected.

I do not know why in the Government of India Press in Koratty in Kerala, 27 employees were dismissed during the emergency. Sometimes I find it with great unhappiness. I know the Ministers are over-worked. Sometimes even in matters of vital importance drafts are signed without locking into them. The position is that 27 persons had lost their job during the emergency. They went to Kerala High Court and the Kerala High Court gave a judgement in their favour. Now what the Central Government has done about it? They have come in an appeal to the Supreme Court. These people who are out of job, are not being reinstated and you are asking them to come to Delhi to fight their cause, to defend the appeal.

I wrote to the hon. Minister about it. May I remind him about that. I

hope he has read the letter before he signed if saying that Articles 14, 16 and 19 are involved? As three articles of the Constitution are involved, therefore, the matter should be decided finally by the Supreme Court. In these cases, where emergency victims have been reinstated, you have not gone on interpretation of Articles 14, 16 and 19. On anything and on every matter, the job of professional lawyers like us is to raise all sorts of difficult questions. It is not difficult for us to work on something and raise any number of questions. But after all, this is a matter which involves your own Government's policy. May I appeal once again with great earnestness, sincerity and seriousness that please look into their records and see what they have been found guilty of before they were dismissed. Please do not go by your legal cell; do not go by an academic exercise of the constitutional provisions. May I appeal to you that this is a serious matter which concerns the citizens of India who were victims of emergency? Please do not continue to keep them as continued victims under your administration. Since the time is short, may I request the hon. Minister.....

MR. CHAIRMAN: You wind up because I have to call the Minister.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: If you allow me, I shall go on.

MR. CHAIRMAN: There is no question of allowing.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: There are some complaints about the National Building Construction Corporation. There are serious charges of corruption which have been brought against them. I request the hon. Minister to look into this matter also because I believe that the reports about the complaints have already been sent to him. Therefore, please have an investigation made about it. Thank you.

निर्णयन और श्रावणस तथा पूसि और पुष्यर्षि मंजी भी (सिफ्तर बस्त) : मुझे खुशी है कि एषान के धानरेबन मैम्बंड ने उन कामों के लिए जो येरो मिनिस्ट्री के मातहत हैं काफी दिवसस्थी का इजहार किया है। हमारे नीजबान साथी जो वहां बैठते हैं और जो मौजूद नहीं हैं उन्होंने तो इन कार्यों को कुछ एजाउ बकलने के लिए कुछ इजाफे का भी जिक्र किया था। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा बराहरेरास्त न सही बिल वास्ता एक इत्लुक उन महकमों से बन जाता है।

मैंने हर धानरेबल मैम्बर की तकरीर को बहुत गौर से और तबज्जह से सुना है। मैं यकीन दिवाना चाहता हूँ कि धगर कोई मुझ से बात जबाब देने से रह जाए तो यह न समझा जाए कि मैं एक बात को दूसरी के मुकाबले में ज्यादा धरम समझता हूँ या मैंने समझा है। फिर भी धगर किसी के जहन या मिजाज पर गिरां मुजरे तो मैं पहले से माबरउ मांगे लेता हूँ।

कुछ बातों पर थोड़ा सा ताज्जुब होता है। जनता सभर्नमेंट का दृढ़ विश्वास है कि जम्हूरियत उस वकत तक फनप नहीं सकती है जब तक कि नुकताधीनी और धालोचना न हो। लेकिन सियासी फलसफादानों ने यह भी कहा है कि नुकताधीनी तामीरी होनी चाहिए, धालोचना रचनात्मक होनी चाहिए। उससे हटने के बाद यह लगता है कि धालोचना सिर्फ धालोचना की खातिर की जा रही है। यह किसी तरीके से भी जम्हूरियत की कर्दों की मददवार नहीं हो सकती। कुछ तो हो जाते हैं उत्कत में जुनू के धासात, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। हमारे नीजबान साथी ने यहां जिक्र किया था कि हाउसिंग की प्रोबलम बहुत बड़ी है हिन्दुस्तान में। उन्होंने कुछ फ्रिगर्स बिये थे। वह जडन धाधमी हैं लेकिन बदकिस्मती से फ्रिगर्स के मामले में वह धापी बालिय नहीं हुए। उन्होंने

दुस्त फ्रिगर्स नहीं दीं। उन्होंने कहा था कि 4.5 मिलियन का बैंक लोग है, जब कि दरघास्त बैंक लोग 15.6 मिलियन का है। यह बात उन्होंने सही कही थी कि धगर 20 साल में मकानात के सिलसिले को फैलाया जाये और बनाये जायें और कोई खानवान बवैर घर के न रहे तो 50 लाख मकानात खानवाना बनाने होंगे। जाहिर है कि बहुत बड़ी चीज है। तीनों कैटेगरीब हैं, बैंक लोग भी है, जिन मकानों को रिलेस करना ही यह भी है, और बड़ती हुई धावादी के लिहाज से भी जो ऐस्टेट मकानात बनाने की जरूरत हो वह सब उसमें शामिल है। हमने कमी दावा नहीं किया कि 50 लाख मकानात बनाने का तकावा पूरा किया जा सकता है रिसेसॉज से बा जो भी चीजें रखी जायें उसके एतबार से। लेकिन जो मैंने कहा कि कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं यह इसलिये कहा कि इतनी बड़ी प्रबलम है और उसके सिलसिले में काफी कुछ ऐसी बातें कह दी जायें कि जिसके सिद्ध में सिक्क इतना कह सकता हूँ कि जिन मोडों की तरफ हम जाते हुए कतराते हैं, कोशिश करते हैं कि उन बातों का जिक्र न किया जाये जो इमरजेंसी के दौरान हुई हों। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस तरफ खींचने की कोशिश की जाती है।

यह ठीक है कि पिछले 19, 20 महीने जो इमरजेंसी के दौरान इस मुस्क ने देखे हैं वह तारीख करामोब नहीं कर सकते। यह भी मुमकिन है कि बावजूद कोशिश के धगर उसका जिक्र न करने की कोशिश की जाये कभी-कभी सुखन मुस्ताराना बात मकते में धा ही जाती है। मैं सिर्फ इतना धरं कसवा कि फारसी की एक बस्त है धाफ्ताने धामद, दलील धाफ्ताने। सूरज जब निकलता है तो दलील देने की जरूरत नहीं होती है कि सूरज धा गया है। सूरज धपनी दलील खुर होता है। रोसनी फेनी हुई हो और जब यह की जाये कि धंधेरा छया हुआ है तो फिर उससे क्या दलील की जाये। और इसलिये

[श्री सिकन्दर बहल]

मैंने कहा "घौर कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।"

हमारे साथी दो चीजों को सामने रख कर यह देखें कि इस साल भर में क्या हुआ है, घौर फिर मैं उनसे इन्साफ़ पर आधारित राय रखने की दबावस्त कर्कं तो मुझे यकीन है कि जो राय उन्होंने अपनी तकरीरों में आहिर करने की कोशिश की है उसको बदलने के लिये खुद ही तैयार होंगे। दो मोटी मोटी चीजें थीं। एक तो यह है कि मंस था जो लीनेसी में मिला, जिसका मेरे साथी ने जिक्र किया। बस्ती की बस्तिवां उबड़ी हुई थीं, खुद एतमादी खतम हो चुकी थी इस पसमंजर में। घौर दूसरे मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा कि जहां तक हमारे साथी माननीय पासवान जी गये धफ़तरभाही का जिक्र करते हुए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस मुन्क के धाजाद हो जाने के बाद पहली मर्तबा धफ़तरभाही को तजुर्बा हुआ कि हुकूमत बदली, दूसरी किसम की सियासी ताकतों के हाथ में इक्तिदार धाया। जाहिर है कि 30 साल से जो संस्कार बन चुके हैं उससे धनम हो कर उनका जहन हमारे जैसा बने उसमें बक़्त लगेगा, दिक्कत होगी। इस पृष्ठभूमि में मैं कुछ फिगर्स रखूंगा घौर मैं धाशा करता हूँ कि उनमें हवाई बात नहीं होगी। मैं सिर्फ यह धाशा करता हूँ कि एक राय कायम करते हुए इन्साफ़ से काम लिया जायेगा।

कहा गया है हाउसिंग की पालिसी के सिलसिले में कोई सैस धाफ़ बायरेक्शन नहीं थी। धब माननीय सदस्य यहां होंगे तो मैं उनसे धबं करता। पांचवें प्लान में 600.92 करोड़ का धाउट-ले था, छठे प्लान में 1538 करोड़ का धाउट-ले है, डाई गुना है। धब मैं यह कह नहीं सकता, हमारे माननीय सदस्य यहां होते तो उनसे धबं करता कि कोई विभा नजर धाई या नहीं?

एनुधन धाउट-ले पर भी मैं चाहूंगा कि तबज्जह दें। 1974-75 में 63.44 का धाउट-ले था, 1975-76 में 90.81 का धाउट-ले था, 1976-77 में 110.08 करोड़ का धाउट-ले था घौर 1977-78 में 163.71 करोड़ का धाउट-ले था जो गुजर गया घौर धाइन्दा साल के लिये 205.52 का धाउट-ले है। मैं पूछना चाहूंगा कि नये तरीके धबतियार करने से कोई विभा बदली हुई नजर धाती है या नहीं?

धापने देखा होगा कि जो रिपोर्ट्स संकुनेट की गई हैं उसमें साइड्स एंड सर्विसेज एक प्रोग्राम रखा गया है। एक साहब ने दुस्त कहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट की कोशिश से इस मुन्क में मकानात की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिये मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जितनी मुमकिन एजेन्सीज हो सकती हैं, जिसमें ब्यक्तिगत लोग भी शामिल हों घौर मुकतलिफ किसम की कंस्ट्रक्शन एजेन्सीज भी शामिल हों, उन सब को शामिल कर के मकानात की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाये। इसके लिये साइड्स घौर सर्विसेज का प्रोग्राम रखा गया है। जमीन डैवलप हो, प्लाट्स लोगों को दिने जायें, खुद लोग मकान बनायें। हमारे बहत से साथियों ने धबन एंड करल डैवलपमेंट का जिक्र किया है। धागे चलेंगे, तो मानूँ होगा कि करल डैवलपमेंट में इस बात पर इस्तरा है कि किस कइ तरक्की हो, लेकिन यह जो साइड्स घौर सर्विसेज का प्रोग्राम है, यह धबन घौर करल दोनों एरियाज के लिये है। जैसे कि धबं किया कि इंस्टीट्यूशनस घौर इंटीविजुअल्स दोनों को इन्वाल्व करना है ताकि वे हमारे इसमें मददगार हों।

धासतौर पर जितने भी गवर्नमेंट के प्लोट किये हुए प्रोग्राम होंगे, उसमें यह फैसला हो चुका है कि पब्लिक फंड से मकान बनेगा तो इकनामिकली बीकर डैवलप घौर जो-

इनकम ग्रुप के लोगों के लिये बनेगा। मेरे साथी ने अभी बयान किया था कि हम जो जनरल पूल के मकानात बना रहे हैं मर्वनमेंट सर्वेन्ट्स के लिये उसमें फिलहाल 1, 2, 3 टाइप के मकान बनाने का फैसला किया है और सिर्फ नीचे की श्रेणी के लोगों के लिये मरद कर सकेंगे।

ब्लक फाइनेन्स एसिस्टेंट, जैसे ए०० धाई० सी० से कर्ज, बैंक से कर्ज और दूसरी स्कीमों से कर्ज यह सब नीचे की श्रेणी के लोगों के लिये होंगे। बैंकों से ई०० डब्ल्यू०एस० हाउसिंग, होस्टल के लिये, रूलर हाउसिंग के लिये, स्वयं क्वीपरेन्स के लिये और हाउस फार ग्रेड्यूएल्ड कास्ट्स और ग्रेड्यूएल्ड ट्राइब्स के लिये कर्ज दिये जायेंगे। यह मेरे दोस्त ने कहा था, मैं उनको बताना चाहता था।

उसके धलावा कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमारे मुल्क में हैं। हमारी बहुत हिम्मत धकबाई उनसे बात करके हुई। कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी उन्होंने सेक्शन धाफ सोसाइटीज के लिये हमारी शरायत पर मकान बनाने के लिये तैयार हैं और हमारी ही शरायत पर हायर-पब्लिक पर लोगों को देने के लिये तैयार हैं।

बीघरी बहुराशकास साहब यहां तमारीफ नहीं रखत हैं, को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा इन्बाल्व करना चाहते हैं, यह दुस्त है। क्योंकि एक धर्सा हुधा, दिल्ली में जो एक्वायर्ड जमीन है, उसका स्टॉक काफी कम हो गया है। इसको सामने रखते हुए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रंसला किया था कि नई को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज को रजिस्टर नहीं करना है। इस बारे में और किया जा रहा है कि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज और ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज को इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्बाल्व किया जाये।

मेरे साथी ने जेनेरल पूल एकोमोडेशन का जिक्र किया है। उसके मुतालिक मैं सिर्फ इतना दोहराना चाहता हूँ कि हमारे पास महदूद सम्पत्ति है, सीमित रीसोर्सिब हैं, जिससे हम इतने बड़े टान धाईर का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग एजेंसीज इन्बाल्व हों, बल्कि हम ने कोशिश की है कि मकानात के प्लिच एरिया, साइज, को कुछ छोटा कर दिया जाये। इसमें कोई शक नहीं है कि छोटा मकान उतना धारामदेह नहीं हो सकता है, जितना कि बड़ा मकान होता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मकान न होने से छोटा मकान होना कहीं बेहतर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धपने समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामकानियत से बचा कर मकानों में ले जा सकें। यह एक बहुत बेहतर चीज होगी। उसके लिए हमने प्लिच एरिया का सिलसिला शुरू किया है।

यहां पर जिक्र किया गया है कि रूलर एरियाज में नैडलैस लोगों के लिए मकानात ऊंची जगह पर बनाये जायें। यह दुस्त है कि इस मसले को ऊंची धीर नीची जगह के नुक्ता-ए-नजर से नहीं देखा गया है। लेकिन नैडलैस लोगों के लिए हाउस-साइड्स का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें यह एहतियात रखी गई है कि वे ऐसी जगह न हों, जहां रहना नामुमकिन हो। नीची जगह के इशारे से मैं यह समझ सका हूँ कि शायद उन लोगों को वहां रखा जाता होगा, जो जगह फ्लडिड हो जाती है और उन लोगों को तकलीफ होती है, और बेहतर जगह बचाई जाती होगी। नैडलैस के लिए हाउस-साइड्स के बारे में एहतियात रखी जाती है कि उन्हें ऐसी जगह दी जाय, जो मुनासिब हो, नामुनासिब न हो।

हमारे यहां कई तजुर्बात और एम्सर-साइजिब जारी हैं कि रूलर हाउसिंग के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है। हमारी एक धारणाइन्बेसन, नैशनल

[श्री सिकन्दर बख्त]

बिल्डिंग धार्यनाइजेसन. ने ऐसे मकानात डेवेलप किये हैं—काफ़ी धक्के मकानात हैं—, जो 1500 रुपये की कीमत के अन्दर अन्दर बनाये जा सकते हैं। उनमें एक खूबसियत यह है कि उनमें जिस मिट्टी से लिपाई हो, वह मिट्टी वाटर-प्रूफ कर दी गई है, वह रेन-रेसिस्टेंट है, बारिश से उसमें इरोजन नहीं होता है। एक धीरे नई चीज यह निकाली गई है कि फूस के छप्पर पर एक सालूगान को छिड़ाने दें, तो उसमें प्राग नहीं लग सकती है। यह कोशिश जारी है, धीरे यह कोशिश खालिसन करल हाउसिंग के सेक्टर को तस्कीन पहुंचाने के लिए है।

हाउसिंग बोर्ड करीब 17 स्टेट्स में बन चुके हैं। यह बात खुली हुई है कि हाउसिंग बुनियादी तौर पर स्टेट सेक्टर में है। हमने यह देखा है कि किस तरीके से सेंट्रल यवर्नमेंट की हिदायत धीरे माइड-नाइन्ड पर धमक हो। कोशिश की जा रही है कि जिन स्टेट्स में हाउसिंग बोर्ड नहीं हैं, वहां भी हाउसिंग बोर्ड कायम हो जायें।

जो कंट्रोलिन्ड प्राये हैं, उनमें एक सवाल यह भी है कि इनकम के मामले में हाउसहोल्ड इनकम का कन्वेण्ट होना चाहिए, यानी अगर एक खानदान में बाहर धीरे बीबी दोनों कमाते हैं, तो उन की इनकम को क्लब करके देखा जाये कि वे कौन से ग्रुप हाउसिंग के लिए एनटाइटल्ड हैं। हम ने तय किया है कि हमारी हाउसिंग स्कीम्स का 75 फ्रीसदी बेनिफिट उन लोगों को जायेगा, जिनकी क्लब की हुई हाउसहोल्ड इनकम 350 रुपये माहवार है, हमारी स्कीम्स का 15 फ्रीसदी फायदा वे लोग उठावेंगे, जिनकी घामदनी 351 रुपये से लेकर 600 रुपये माहवार तक है, धीरे 10 फ्रीसदी फायदा वे लोग उठावेंगे, जिनकी घामदनी 601 रुपये से 1500 रुपये माहवार है।

श्री राम बिलास पालवान : धीरे जो बोमस सार्टिफिकेट देते हैं इनकम का।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरी मिनिस्ट्री के मातहत कोई ऐसा महकमा नहीं है कि जो बोमस सार्टिफिकेट की तहकीकात कर सके। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री राम बिलास पालवान : मैंने एक एम्बाम्पल प्राय के पास लिख कर दिया था जिसमें बोमस सार्टिफिकेट प्रोव्यूस किया गया था। यह जो सो इनकम ग्रुप धीरे दूसरी कौटेगरीज प्राय ने रखी है उसमें लोग बोमस सार्टिफिकेट दे देते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं सवालों का जबाब देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं चाहूंगा कि धाखिर में ये सवाल करें तो धक्का होगा।

इसके अलावा मैं अर्थ कंसर्वा फिन्सांटे-शन वर्कर्स के लिए मकानों की सुविधा पैदा करने की बात सेंट्रल सेक्टर में है धीरे यह अनाहिदा से पैदा की जा रही है।

स्टेट स्कीम्स के मातहत कितनी ही स्कीम्स हैं जो कि मकानात की समस्या से ग्रिपल कर रही हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सभिसाइड्ड स्कीम्स हैं। 20 परसेंट सभिसडी के साथ उनके लिए मकान बनने धीरे उनमें उनको किराए पर रखा जाता था। मैं फखिया यह कहना चाहता हूँ कि इसी छोटे धरते के अन्दर जनता चाटी का इरादा यह है कि जो हुकूमत के बारे को कम से कम रखती है वह बेहतरीन हुकूमत होती है। जनता गर्बनमेंट की ऐसी अनाहिदा नहीं है कि हम जमींदारी की अहमियत रख कर मकान बनायें धीरे खुद अग्रणी मिस्किपल कायम रखें धीरे लोगों को किराएदारी पर रखें। अबादा से अबादा ताबाद में हम इस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे बुझे यह अर्थ करते हुए फक महसूस हो रहा है कि यह जो

सबिन् डाइज्ड स्कीम थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जहां सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिटायर एंड की हैसियत से धारक रह सकते थे और रिटायरमेंट के बाद जिनको उमे खाली करना पड़ता था उम स्कीम में यह फैसला कर लिया गया है कि 20 परसेंट मजिस्ट्री के बाद वह मकानात इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बेच दिए जायें, उन को दे दिए जायें।

स्टेट सेक्टर में एकोनामिकली वीकर सेवमंग के लिए स्कीम है। लो इमकम ग्रुप के लोगों के लिए स्कीम है, मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए स्कीम है, रूरल हाउसिंग स्कीम है। प्लाट डेवलप कर के साइटस एंड सबिसेज की स्कीम है। दिवेंज हाउसिंग स्कीम बिचकुल एक प्रलहिदा प्रोजेक्ट है जो हर स्टेट के पास है और वह उस पर काम कर रहे हैं। इसमें खास तौर से यह क्राबिले तबग्जह बात है कि प्रगर मकान की कीमत पांच हजार की हद के अन्दर है तो 80 फीसदी लोन इस किस्म के मकानात बनाने के लिए देते हैं। दोबारा यह सुविधा सिर्फ रूरल सेक्टर में दी जाती है।

कुछ यूना तकरीरें खास तौर से दिल्ली को सामने रख कर हुई, डी०डी०ए० का बिज करले हुए हुई। मैं पिछलो सारीख में जाने से बहुत बचता हूं लेकिन वह बुकस्त है कि डी० डी० ए० जिस हाथ में हम को मिला उसको संभालते संभालते क्यों लग सकते थे। लेकिन उसको संभालने में काफी तेजी से काफी नई बातें पैदा हुई हैं। मैं मुन्तरसन बन्धी जल्दी कुछ बातें बताना चाहूँगा। डी०डी०ए० की एक सबसे अग्रानक तकलीफ लोगों को यह थी कि वहाँ बिसेज होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। लोग अकसरान नक पहुंच नहीं सकते थे। न मामूब कितनी मजिधलों में कई कई दिन और हफ्तों जाने के बाद हाबिरो का मौका मिलना था। इस वकत यह कंफिमत पेदा कर दी गई है कि डी०डी०ए० के किसी बड़े से बड़े अकसर तक पहुंचने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। अग्राम के मजदूरों का कर वे लोग काम कर रहे हैं।

इस सिलसिले हिवायत में वे दो गई है।

वह धो दुकस्त है कि डी० डी० ए० का बजद जित बीज को बुनिबाधी तौर पर सामने रख कर प्राया था वह यह था कि जो एक लार्ज स्केल एक्सीजीशन अफ लैंड हुआ था दिल्ली में उसमें अमल मुद्रा और मकमद जो सामने रखा गया था वह यह था कि यह कालोनाइजर्स जमीन के मामले में बहुत कारो-बारी जेहनियत रख कर बहुत मुनाफाखोरी कर रहे हैं। डी० डी० ए० ने न सिर्फ यह किया कि उन जमीनों के मुताबिक सिर्फ उतना किया कि कालोनाइजर्स ने कारोबारी जेहनियत बारी कर लिया और खुद उसमें लग गए बल्कि पहले वह कालोनाइजर्स उस किस्म के काम नहीं कर सकते थे जो डी०डी०ए० ने किया। यह मेरे लिए तो एक बेइन्तहा ताज्जुब की बात थी कि दिल्ली में एक हजार गज का प्लाट 2 करोड़ और कुछ लाख में बिका। बीस हजार रुपए गज से कुछ ज्यादा पर वह बिका। अब इस किस्म के तरीके बनाए गए हैं कि डी० डी० ए० की कार्याशियस ऐक्टिविटीज खत्म हो जाय और यह जो मैनिमेट न्यूट्रिटीटी का एटीटयुड डी डी ए ने बखियापार कर रखा था उसको खत्म करके उस संस्था का री-ओरिएंटेशन किया जाये ताकि लोगों की बिदमत का वह एक इदारा बन सके। मकानात के एक्सपैशन के सिलसिले में इजाफा करने के सिलसिले में अकसर वी कि नकसे जना किये जायें और फिर उनमें नदीनों बरखों लोभ लटके रहते थे। उसके लिए एक मुकम्मल फार्मुला बना लिया गया है, स्टैंडर्डाइज्ड प्लान बना लिया गया है जिसकी हिदायतों के माझहूत रहते हुए टायरी कर सकते हैं, डी डी ए के पास धाने की अकसर नहीं है। यही सूरत इन्ट्रिच माडीफिकेजन्स के लिए भी है, स्टैंडर्डाइज्ड प्लान के अन्तर्गत निर्माग किया जा सकता है। पहले मकानात के कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अकरीबन नामुशकिल था, 10-15 वर्ष में नहीं मिलता था। उसका तरीका भी बिचकुल सिम्पलीफाई कर दिया गया है।

[श्री सिकन्दर वक्ता]

घर सवाल यह है कि डी डी ए के मासहत मकानात किसने बनाने चाहिए। जनता गवर्नमेंट के बरसरे एक्विटदार होने से पहले घासतन जो मकानात बनते रहे हैं वह तीन चार हजार सालाना बनते रहे हैं। जनता गवर्नमेंट ने अपने सामने टार्गेट रखा है कि 40 हजार मकानात हर साल बनाने चाहिए। वह बहुत बड़ा टार्गेट है। इसमें सिर्फ डी डी ए की ही बाध नहीं है। इसमें से 10-12 हजार सालाना मकानात बनाने की जिम्मेदारी डी डी ए की है। धीरे जैसा मैं ने शुरू में धर्ज किया था यह मकानात सिर्फ तो इनकम ग्रुप में एकोनामिकली बीकर सेक्शन के लिए बनायेंगे। 10 हजार के करीब मकानात, जैसा मेरे साथी ने धर्ज किया, हर साल सेन्ट्रल पी डब्ल्यू डी जनरल पूम में सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज के लिए बनायेंगी। इसके अलावा 20 हजार मकानात प्राइवेट कॉन्स्ट्रक्शन एजेंसिज, ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज और कोऑपरेटिव सोसायटीज के जरिए से कनेंगे।

इसके अलावा एक धीरे भी बीच हमारे इहन में है जिस पर एक्ससर्टाइज हो रही है धीरे जिसको हम एन्करेज करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है, वह अपने एक हजार एम्पलाईज के लिए मकान बनाना चाहती है तो उसको हम मकान बनाने के लिए जमीन देंगे। हमारे साथी शायद चले गए, उन्होंने कहा कि पोस्ट एंड टेमीग्राफ डिपार्टमेंट अपने मोहकमे के लिए मकानात बनाना चाहता है तो मैंने कहा बेलकम है, हम जमीन देंगे, प्राप मकान बनायें। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हम एन्करेज करना चाहते हैं। इस तरह से यह काफी बड़ा टार्गेट है। कुछ तादाद दुकानात की भी है। करीब एक हजार मकानात हर महीने में डी डी ए को रिस्वीज करना चाहिए। साइट्स एंड सबिसेज का प्रोग्राम मैं पहले धर्ज कर चुका हूँ। डी डी ए के मकानात काफी मंहने बनने लगे हैं धीरे हकीकत यह है कि जहाँ तक लेबर की कास्ट का टाल्लुक

है, जहाँ तक बिल्डिंग मैटीरियल की कास्ट का टाल्लुक है, मकानात का निर्माण करने वाले मजदूर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग मैटीरियल में किस किस की इन्फ्लैटियन कर सकें उस किस की एक्ससर्टाइज हो रही है। मकानात का प्लान एरिया कम किया जा सके, उस किस की एक्ससर्टाइज हो रही है। इन्फ्लैटियन के कम कीमत के मकानात के नामसे कायम किए हैं मसनन ई डब्ल्यू एस का मकान 8 हजार की रेंज तक बनाने का खयाल है, एल घाई जी का मकान 18 हजार की रेंज तक बनाने का खयाल है धीरे मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 42 हजार की रेंज में मकान बनाने का खयाल है। मैं ध्रापते धर्ज करूंगा कि मिडिल इनकम ग्रुप का मकान 30 हजार या उसके ऊर्ही पड़ोस से पड़ूंच गया था। इसी तरह से धरार खयाल सही है तो एल घाई जी में 70 हजार तक का सिलसिला था। इन्फ्लैटियन के नामसे को सामने रखते हुए डी डी ए न फँसला किया है कि तीनों ग्रुपों में हल्समकान इन्ही कीमतों में मकान बनाने की कोशिश की जायेगी।

धाम तौर पर एक त्रिकायत यह रहती है कि डी डी ए ने जितनी नयी कालोनीज का निर्माण किया है उनमें सिबिक एमिनिटीज पूरी नहीं हो सकीं। इस लिये उन इलाकों को म्युनिस्पिस कारपोरेशन ने टेकओवर करने से इन्कार कर दिया है, क्योंकि उन कालोनीज में सीबर उन के स्टैंडर्ड के मूनाबिक नहीं था। एक स्कीम इस किस की शुरु कर दी गई है कि इन कालोनीज में जो इनएडोम्बेसीज हैं, उन को खूब किया जाय धीरे उन की डबलपमेंट की शुरु पूरी करने के बाद उनको म्युनिस्पिस कारपोरेशन को सौंप दिया जाये। इस सिलसिले में एक टेक्नीकल-सेल बना दिया गया है जो लेफटीनेट गवर्नर की देखरेख में, जो डी० डी० ए० के चेयरमैन है, काम कर रहा है।

जमीन की कीमतों के बारे में मैंने धर्ज किया है कि जमीन की कीमतें प्रयानक हद तक पड़ूंच चुकी हैं। जमीन की कीमतें कम

नों, इस के लिये भी फैसला किया गया है, कन्सलटेशनस चल रही है और यह मसला भी एक कमेटी के बारे-गौर है कि किस तरह से इन को नीचे लाया जा सकता है। हम अभीन भी कीमतों को नीचे लाने के लिए कमिटेड है।

हमारे एक भाई ने जिक्र किया कि जो रिसेटिलमेंट कालोनीज बनाई गई हैं उन की हालत बहुत खराब हैं। यह सही है कि अगर दिन के बक्त, जब कि सूरज ठीक सिर पर हो, अगर ध्राप उन कालोनीज के अन्दर चले जायें तो ध्राप की महसूस होमा कि शायद उस बक्त रात के 12 बजे है। उन मकानान में रोशनी की किरण बिलकुल नहीं जाती है। लेकिन यह मसला इतना बढ़ा है कि उन को नये सिरे से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यह कोशिश जरूर की जायेगा कि उन की मौजूदा तकलीफ को कम किया जाये।

धन-धाराचौराइज्ड कालोनीज के बारे में हम कमिटेड हैं कि उन सब को रेगुलराइज किया जायेगा, लेकिन सिर्फ उनको किया जायेगा, जो एमरजेंसी के अन्त होने के पहले-पहले बन गई थीं। यहां पर एक बात में मौदिवाना तीर पर धरं करना चाहता हूँ—एम जेंसी के बाद धनधाराचौराइज्ड कन्स्ट्रक्शन का होना दुस्त नहीं है, उस को हटाने के लिये हय मज दूर होंगे, क्योंकि जब हम हाउसिंग एक्टिविटीज को हटने गुना बढ़ा रहे हैं, तब भी यह चीज जारी रहे, कायदे-कानून का पूरा अहत धाम व किया जाये—यह दुस्त बात नहीं है। इस लिये जितनी धनधाराचौराइज्ड कालोनीज एमजेंसी के पहले की हैं, उन कालोनीज को रेगुलराइज करने के लिये एक हार्ड-लेबल कमेटी बनी हुई है, जिस के सत्र लेफ्टिनेन्ट गवर्नर साहब हैं और मैं समझता हूँ कि रेगुलराइजेशन का काम बहुत जल्द शुरू हो जायेगा। इस सिमिलिस में एक एकाबट नक्शे के बारे में पैदा हुई थी, लेकिन उस को भी हल करने की कोशिश कर ली गई है।

श्री ब्रह्म प्रकाश जी इस बक्त यहां मौजूद होते तो धरंका था। उन्होंने मास्टर प्लान का

जिक्र किया था। जो मास्टर प्लान इस बक्त चल रहा है, शायद उन की मुराद उसी से है। पिछले एक साल में मैंने यहाँ आकर उसकी कैफियत देखी है। वह मास्टर प्लान अगर सब से ज्यादा जकमी किसी से हुआ है, तो वह गवर्नमेंट के अंगों से हुआ है, उस की शकला-सूरत बिगड़ चुकी है। लिहाजा यह जरूरी है कि दिल्ली के लिये एक नया मास्टर प्लान बनाया जाये। हमारी मिनिस्ट्री इस बारे में पूरी तरह से सीज्ड है और उस पर एक्सरसाइजेज जारी हैं। जो नया मास्टर प्लान बन रहा है, वह 2001 तक के लिये लागू होगा।

स्लम क्लिअरेंस के बारे में भी मैं मौदिवाना धरं कर्ंगा। एक जमाने में एक बहुत खूबसूरत धरंकी बात सुनी थी। हमारे जमाने के एक नेता थे, जिनके सामने मैंने सिर झुकाया है, उन्होंने कहा था—“मिरा बस चले, तो सब स्लमज को ध्राग लगा दूं।” यह बात सब को धरंकी लगी थी और नौ-जबानी के धालम में हम को भी बहुत धरंकी लगी थी। लेकिन स्लम हट जाये और उनमें रहने वाले माकूल तरीके से बसाये जा सकें—ये दोनों चीजें साथ चलना जरूरी है। बड़े शहरों में इस बक्त दो तरह के स्लमज हैं। एक तो ये हैं जिनमें झुग्गी-झोपड़ी में लोग रहते हैं और दूसरे ये हैं, जिनमें पुरानी इमारतें हैं। दिल्ली की ही मिसाल में ध्राप के सामने रखता हूँ—30 साल पहले एक स्कीम कन्सीब की गई—पुरानी दिल्ली के एक छोटे से हिस्से में—जिसको दिल्ली-अजमेरीगेट स्कीम कहते हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा सिटी का है। ध्राज तक उसकी एक ईंट हटाकर कोई नया डिबेलेपमेंट का काम वहां नहीं हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा मजहकखोजेज पोजिशन अखस्थार की गई है वह यह की गई है कि जो मकानात इस स्कीम में ध्राते थे उनमें से कुछ मकानात की तो एक्वायर कर लिया गया लेकिन बाकियों को नहीं किया गया। ये पत्र-लिखे मकान मासिक थे। एक्विजिशन प्रोसीडिन्स को कंटेस्ट नहीं कर सके। पांच सात हजार की

[श्री सिकन्दर बख्त]

छोटी रकम फँसला करने के बाद जमा कर दी गई ट्रेजरी में और खुद घालिक बन बैठे एक दूसरा पहलू बहुत धजीब हैं। मकानों की एक पट्टी की पट्टी एक्वायर नहीं की गई। पूरा का पूरा इलाका डेबलप करना था तो सो दो सो एक ही पट्टी के एक्वायर किए जाते लेकिन एक यहाँ किया दो तीन वहाँ कर लिए गए। समझ में नहीं आता यहाँ जिस ज़हन से काम हुआ। दूसरा तमाशा यह था कि कभी डी० डी० ए० के पास या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास या एवेंमेंट प्राफ इंडिया के पास इतने रिसोर्सिभ नहीं हुए कि दिल्ली-प्राजमेरीमेट स्कीम के पूरे मकानात को गिरा कर उसकी जगह नए मकानात का निर्माण किया जा सकता है। उसके बावजूद भी कुछ मकानात एक्वायर करके मकान मालिकों को किराएदार करार दे दिया गया और पांच हजार घयर एक्वायर करने का कम्प्लेसन दिया तो उन पर पन्चीस तीस हजार रुपया किराए का निकास दिया। शजीदयी के साथ हमारी मिनिस्ट्री ने सोचा है इस मामले पर कि यह जो पुराना सहर है यहाँ जो मकानात हैं उनके पुराने डाकों को बदलना करीबन नामुम्किन है इन दी फेस प्राफ टू फेक्ट्स। एक तो बैसा कहा सहर में मकानात की समस्या इतनी बड़ी है कि बीस साल में घयर हमको इसको पूरा करना है, सब कुछ पूरा करना है तो पचास लाख नए मकानात बनाने होंगे। ये हम नहीं बना सकते हैं। कुछ मकानों में—कुछ लोभ रहते हैं, उनको निकाल कर नए मकान बनाने का इराबा कर रहे हैं। रुपया पैसा पास नहीं है तो क्या किया जाए? इस किस्म की एक्सरसाइज हमारे यहाँ जारी हैं कि पुरानी दिल्ली के मकानात की बाहर की ज्योडाफी कामय रहे लेकिन साथ साथ वहाँ ले लोभ उन मकानात में घावादी के साथ मुरम्मत कर सकें, इनमें इजाफा करना हो तो वह कर सकें, उनको बदल कर नया बना लेना चाहते हों तो उसके लिए लाजिमी गर्त सिर्फ यह है कि बना तो

झकते हैं लेकिन बाहरी ज्योडाफी मकानों की जो है वह कामय रहे। इन तमाम तामेयों के सिलसिले में उन लोगों की बर्बन पर म्युनिसिपल कारपोरेशन के बाहमाव की तनवार न लटकी रहे। ये तमाम मकानात जो कम्बल होने वाले हैं, गिरने वाले हैं, खंडहर बनने वाले हैं, उससे इनको बचा सकते हैं और मकानों की जो समस्या हैं पुराने मकानों को गिराकर उसमें तब इजाफा करने की जरूरत बाकी नहीं रह जाएगी। मेरी मिनिस्ट्री में इसके बारे में एक एक्सरसाइज जारी है। उसमें कौन सी कानूनी सुरत पैदा की जा सकती है कौन सी नहीं, इसको देखा जा रहा है। मैं शुरु में कह चुका हूँ कि यह हकूमत घपने दायरे हकूमत को कम से कम करने में यकीन रखती है। उसको सामने रखते हुए जो बात बताई थी उसके अलावा एक बात यह भी है कि जो रिफ्यूजी माकिट्स यहाँ दिल्ली में कुछ थी, उनके बारे में फँसला कर लिया गया है कि घासान किस्तों पर उन माकिट्स में खोनरशिप उनको दे दी जाए। जो रिफ्यूजी कामोनीज वहाँ भी उनके बारे में भी फँसला कर लिया गया है कि उसकी खोनरशिप भी घासान किस्तों पर ह्युर परचेज पर उनको दे दी जाए। यह भी फँसला कर लिया गया है कि रिफ्यूजी कामोनीज में एक एडीकेशन स्टोरी उनको बनाने की इजाजत दे दी जाए। इसके अलावा डायरेक-शंस का मैं कुछ जिक कर रहा था उसको भी याननीय सवस्य जो था वह है बोधा पड़ लें।

एबरवेंसी के फौरन बाद जो हीफियत पैदा हुई थी वह यह थी कि बस्तियों की बस्तियाँ उबड़ी हुई थीं और जनता गर्बनमेट ने यह फँसला किया है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों से बितने लोभ भी हटाए गए हैं। बितनी बस्तियाँ भी डिमांडिब की गई हैं वुम-डोज की गई हैं उन सब बस्तियों में स्टेट्स की हेंटी ऐस्टेबलिश किया जाएगा। और इस बोधे घस में, मैं यह कह के साथ कहना चाहता हूँ कि मोतीनगर में बहुत बड़े रैमाने पर डिमो नीकमस हुए थे, वहाँ स्टेट्स को ऐंटी ऐस्टेबलिश करने का सिलसिला हो चुका है करीब करीब

कुछ जारी है। धर्जन नगर एक बस्ती है, उस बस्ती पर करम एक साहब का हुषा। जिन्हें तो मैं क्या कहूँ, धीरे कुछ समय में नहीं धाया बह ठीक है कि वह धनधोराइज्ज थी, लेकिन धाधी बस्ती निरा दी गई धीरे धाधी धपनी बगह पर कायम रही। कुछ समय में नहीं धाया। वह धर्जन नगर का प्लान मुकॉम्मल हो चुका है। वहाँ भी निर्माण का काम दोबारा फिर शुरू होने वाला है।

तुर्कमान गेट तो इमरजेंसी के जमाने का एक गैर मामूली धीटर है। मैं इस वकत कुछ बहाने ज्यादा उस सिलसिले में जज्बाती बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात पर फ़क़र कर रहा हूँ कि तुर्कमान गेट के रहने वालों को दोबारा वहाँ ला कर बसाया जाये उस प्रांजेट की धाधारशिला प्राइममिनिस्टर के मुबारक हाथों से रखी गई है। उजाड़ना बहुत धासान काम है, लेकिन तामीर के लिए एक ईट के ऊपर एक ईट रखनी होती है। मकानात ज्यादा तादाद में बनें, उजड़ी हुई बस्तियाँ दोबारा बसाई जायें, जिन रिपयूजी मार्केट या कालोनीज के धन्दर मिल्कियत की धावेदारी हकूमत करती रही थी, वहाँ की मिल्कियत रहने वालों को दे दी जाए, कुछ इबेकुई प्रोपर्टी इसलिए तबाह हो रही है कि उनका कोई मामिक नहीं बनने वाला था, डी० डी० ए० उनकी तरफ़ तबज्जह नहीं कर सका, उनके मुताल्लिक यह फैसला किया गया है कि जो उसमें रहने वाले हैं उसकी मिल्कियत उनको दे दी जाये। यह दिशाएँ हैं जिनकी तरफ़ धापकी तबज्जह दिखाना चाहता था।

नेशनल कैपिटल रीजन, जैसा कि चौधरी साहब ने जिन्हें किया था, यका कंसेप्ट मगरिब में बीरो किया गया धीरे इस बीज को सामने रख कर बीरो किया गया कि बड़े बड़े शहरों में धाबादी का दबाव कम हो। हमारे साथी यहाँ कह रहे थे कि निर्माण का काम राजस्थान में सिर्फ़ धलधर के हिस्से

में नहीं बल्कि धरतपुर में भी किया जाये। मैं यह धर्जन कफ़ंगा कि नेशनल कैपिटल रीजन का बुनियादी कंसेप्ट इन तमाम मुकों के निर्माण में सम्बन्धित नहीं था। यह कंसेप्ट यह था कि बड़े बड़े शहरों से धाबादी का दबाव कम करने के लिए सैटेलाइट टाउन्स डेवलप किए जायें। पहली बात तो मैं यह कहूँगा मुझ धकतोस है कि इसकी तरह तबज्जह नहीं की लोगों में। नेशनल कैपिटल रीजन का कंसेप्ट 1961 में बज्जद में धाया। यह देहली से सम्बन्धित है, देहली के इंदगिर्द सैटेलाइट टाउन्स को धाइडेन्टिफाइ किया गया है। लेकिन इस कंसेप्ट के बज्जद में धाने के पहले ज़त यह थी कि जितने इलाके इस रीजन के धातहत हों इन इलाकों पर कोई एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव धाधोरिटी, स्टेट्टरी धाधोरिटी उस पर कारोबार करे धीरे उसका एहतमाम करे। लेकिन इसके लिए मंजूरी लेनी थी तमाम उन स्टेट्स में जिनके इलाके इस रीजन में शामिल थे। हरियाणा ने मानने से इन्कार कर दिया। नीमसी नेशनल कैपिटल रीजन का कंसेप्ट वहाँ धन्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से धीनें तो डिफ़्ट में रहती हैं। 518 लाग ८० इस कंसेप्ट पर सर्प किया गया। टुकड़े-टुकड़े कर के सर्फ़ किया गया। कुछ रुपया धेरठ में लगा दिया गया, कुछ मुधगांध, धलधर धीरे पानीपत में। कतई तीर पर बिल्ली के बुनियादी नेशनल कैपिटल रीजन के कंसेप्ट में कोई तस्कीन नहीं पहुंची। उसके वरफ़स यह हुषा कि नेशनल कैपिटल रीजन के कंसेप्ट की फलाउटेजन जगह-जगह हुई धीरे उसकी सबसे बड़ी मिसाल नौएडा का कथाम है जो कि दिल्ली के विलकुल धीरे-स्टेप पर लाकर रख दिया गया है। नौएडा जैसा कंसेप्ट नेशनल कैपिटल रीजन में बुनियादी कंसेप्ट को बिल्कुल मुकॉम्मल तरदीद है। नेशनल कैपिटल रीजन का कंसेप्ट धल कंसेप्ट सकता था? इसके धाबावा इसकी दूसरी कभजोरी जो ह्यारे सामने धाई, कि इसका एक इन्टेग्रेटेड यूनिट नहीं है जिस पर इसके

[श्री सिकन्दर बघन]

इंतजाम का दखल हो। दूसरी कमजोरी हमारे सामने यह धाई कि धरम कोई ऐसा शहर डेवलप हो किसी बड़े शहर के करीब, बिसे सैटेलाइट टाउन कहेंगे जो बड़े शहर के कम्युटेबल डिस्टेंस में हो तो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्जुमानी नहीं हो सकती और इसलिये नहीं हो सकती कि उसकी मिसाल दिल्ली में मौजूद है। लोग गाजियाबाद में काम करते हैं। गाजियाबाद बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन रहते दिल्ली में हैं। काम करते हैं फरीदाबाद में लेकिन रहते दिल्ली में हैं। अभी हम धाखिरी तौर पर इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जाती राय है, मैं समझता हूँ कि नेशनल कैपिटल रीजन का किसी फार्म में चलते रहना मसत होगा। लेकिन उसके साथ जो यह बड़े शहरों का दबाव है, उसको रोकने के लिये क्या किया जाये ?

हमारे मुक्त में 400 के करीब ऐसे शहर हैं, जिनकी धाबादी एक लाख से लेकर 2 लाख तक है। हमारे हठको के जिम्मे सिर्फ इस किस्म का काम था कि वह मकानात के निर्माण के सम्बन्ध में बर्ज दे दे डिफरेंसियल रेट धाफ इन्टररेस्ट पर। लेकिन इस बफत दो नये काम उनके जिम्मे लगाये गये हैं। एक यह कि करल हाउसिंग के लिए 50 परसेंट लोन दे और इस सम्बन्ध में तीन सुबों से स्कीम बनकर धा चुकी है, केरल, कर्नाटक और पंजाब से। मकान की मैक्सिमम कीमत 4 हजार रुपये हो, यह एक काम उनके जिम्मे नया लगा है करल हाउसिंग को बढ़ाने के लिये।

दूसरा काम यह है कि एक ऐसा छोटा टाउन लाख, दो लाख की धाबादी का धाई-टि-फाई करें कि जो किसी बड़े शहर के कम्युनिकेशन डिस्टेंस में न हो। हो सकता है कि वह धाखिरी तौर पर फँसला किसी ऐसे शहर के बारे में करें कि: दो नेशनल कैपिटल रीजन में हो

हो। इसके बाद धरम किसी एक शहर के डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया जायेगा तो मुकम्मिल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जायेगा ताकि काउन्टर मैननेट बन सके उस धाबादी के लिये जो दिल्ली की तरफ धिचो धनी धा रही है। वहाँ मकान होंगे, बाब धपोरचुनिटी होंगी, एंटरटेनमेंट होंगे, मैडिकल फेसिलिटीज होंगी, एजुकेशन, स्कूल, कालेजेज धनीरूह धनीरूह होंगे। धरम रुपया एक जगह पर सर्फ किया जायेगा ताकि टुकड़े-टुकड़े कर के फाइल का मुंह जो धरा जाता है, वह बात न हो, बल्कि एक एचोबमेंट होती हुई नजर धाये। धरम हम इसमें कामयाब रहे तो इस किस्म की हाउसिंग की एक्सरसाइज सारे हिन्दुस्तान में से जाने की कोशिश करेंगे। हमें धाशा है कि इसके बाद जो बड़े शहरों पर धाबादी का दबाव है वह धकेगा।

इसके धलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, जिसमें कि हम धाजकल मुबतिला है, वह है कि जब लीज कंसेप्ट बजुद में धाया था तो वह इसलिये था कि हमारी हुकूमत के कुछ पुजों की ध्वाहिग धी कि जमीन पर हुकूमत का कंट्रोल रहना चाहिये, धावाम का नहीं होना चाहिये। हाताकि वह भी पीसमील रहा, फीहोल्ड जमीन भी है और लीज-होल्ड जमीन भी है। शायद यह भी इसी नुप्नेनजर से किया गया था कि जमीन पर कारोबारी जहनियत का इखलाक न हो और जमीन की कीमतें न बढ़ें। लेकिन चलते-चलते लीज ने एक धजीबोगरीब मूरत धबलवार कर ली। यह एक मुस्ताकिल तलवार है जो शहरियों की गधेन पर मटकी हुई है। उस तलवार से यही नहीं कि जमीन का कंट्रोल जारी है, बल्कि कई-कई गुना, जब धर्ची होती है वह कीमत बढ़ जाती है। सैकड़ों पर पहुँच जाती है। हमारे यहाँ इस सिलसिले में बहुत सीरियस एक्सरसाइज है। मैं समझता हूँ कि इस में कुछ रकाबटें नखर धा रही है, लेकिन उन रकाबटों को दूर किया जायेगा। जनता पार्टी का धपने

इसबनन में निकेटो में कमिटमेंट है कि लीड खत्म होगा, और लीड खत्म किया जायेगा ।

एक मेम्बर साहब ने धरबन लैंड सीलिंग एक्ट का जिक्र किया । मैं क्या कह सकता हूँ ? धरबन लैंड सीलिंग एक्ट और दिल्ली में बयकवक्त धरबन घाटर्स कमीशन का क्याम, इन दोनों में एक दूसरे की तरदीव नजर आती है । धरर वड़े बड़े मकानात में सरप्लस जमीन है, तो वहाँ या तो मालिके-मकान प्रजबूद बीकर मैकलनज घाफ़ दि सोसायटी के लिए मकान बनये और धरर वह न बनाये, तो वह सरप्लस जमीन ले कर नुकूमत बनाये ।

धरबन घाटर्स कमीशन के क्याम का ताल्लुक सिर्फ़ इस बान से है कि दिल्ली में ऐस्वेटिक्स घाफ़ प्राकिकटेक्चर को कायम रखना चाहिए । मुझे बताया जाये कि यह कैसे हो सकता है । गालिबन धरबन लैंड सीलिंग एक्ट कुछ जल्दी में बन गया । उस का नतीजा यह हुआ कि बिल्डिंग एक्ट-बिटी को सक्त धक्का पहुंचा और वह रुकी । हमने नई गाइडलाइन्ज आया की है, जिन के जरिये धरबन लैंड सीलिंग एक्ट के इस बनियादी कनसेप्ट को कायम रखते हुए कि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं रहनी चाहिए—500 गज से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के खिलाफ़ जो रिगर्ज है, उन्हें कम करने की कोशिश की गई है, और मैं समझता हूँ कि उससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री सौमन्य राय (बैरकपुर) : एक्ट में कुछ डाइरूशन भी हो गया है ।

श्री सिक्न्दर बख्त : डाइरूशन बेसिक कनसेप्ट का नहीं हुआ है, लेकिन डाइरूशन उन रिगर्ज का बेफिनेटभी हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन में रुकावट बन रहे हैं ।

रुलन और धरबन वाटर सप्लाई का जिक्र हुआ है । सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ रिस्ते हैं, कुछ तरीके हैं । जैसा कि मैंने धर्ज किया है, हाउसिंग स्टेट सैक्टर का एक सबजेक्ट है । उसी तरह से ड्रिनिंग वाटर सप्लाई भी स्टेट सैक्टर का एक सबजेक्ट है । स्टेट्स को ब्लाक ग्रांट या ब्लाक लोन की सक्ल में रुपया मिलता है । हर स्टेट को यह प्रज्जयार है कि अपनी जरूरत से मुताबिक प्रापर्टीज रखे । लेकिन मैं मुकनुबार हूँ अपने नौबवान साथी का, जिन्होंने बहुत सी बातों को तो मानने से इन्कार किया, जिन्हें कोई दिशा, डायरेक्शन, नहीं दिखाई दी, जिन्होंने वह नहीं देखा कि ज्यादा से ज्यादा मकानात बनाने का क्या प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने कम से कम इस बात को माना कि हिन्दुस्तान की तारीख़ में पहली बार प्राबलम बिलेजिड का जिक्र हुआ ।

पिछला बजट हम को करीब बना-बनाया मिला था । उस में 40 करोड़ रुपया रखा गया, ताकि प्राबलम बिलेजिड में, सेंट्रल सैक्टर में रखते हुए, पीने का पानी मुहैया करने की चेष्टा की जाये । हमारे एक भाई ने—गालिबन मण्डल साहब से—कहा कि यह प्रफ़्तोस की बात है कि धरमले बजट में 40 करोड़ रुपये के एलोकेशन को घटा कर 38 करोड़ रुपया कर दिया गया है । मैं उन की इत्तिला के लिए धर्ज करूंगा कि 40 करोड़ रुपये को घटा कर 38 करोड़ रुपये नहीं किया गया है, बल्कि उसे बढ़ा कर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह दुस्त है कि इन स्कीम्ज को चलाने के लिए हम को सूबाई मशीनरियों से काम लेना पड़ता है, लेकिन ये स्कीम्ज सेंट्रल सैक्टर में हैं । हमारे दोस्तों ने राजस्वान का जिक्र किया । हम स्टेट्स को कहते हैं कि बताइये, धराप के वहाँ कौन से प्राबलम बिलेजिड है । यह जाहिर है कि यह काम बन स्टोक में नहीं हो सकता है । हमारे वहाँ प्राबलम बिले-

[श्री सिकन्दर बकत]

जिब 1,53,000 है। उन में से 40,000 को पानी मिल चुका है और 1,13,000 बाकी है। हमारी इकानोमी की मौजूदा सूरते-हाल को समने रखते हुए हमारा टारगेट है कि सात साल में यह काम पूरा किया जायेगा। मुझे इत्फाक है कि सात साल तक इन गाँवों को जहाँ पीने का पानी एक मीन की हद के प्रन्दर मुहैया नहीं हो सकता, उन को सात साल तक इंतजार नहीं कराना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेगे कि यह सात साल की मियाद कम की जा सके। उस में बुनियादी इन्फ्रस्ट्रक्चर पर है कि हमारे रिसेसोर्ज कहां तक हम को इसे डायरेक्शन में चलने को इजाजत देते हैं। . . . (ब्यवधान) मैंने हिन्दुस्तान भर का जिक्र किया।

श्री राम बिलस पास्तखान : दिल्ली में तो पानी पीने की कहीं ध्यवस्था ही नहीं है। गर्मों के दिनों में देहात से जो घादमी घाटा है वह कहां पानी पीयेगा ? दिल्ली इतना बड़ा शहर है, यहां जो घादमी देहात से घाटा है जिस की कहीं जान पहचान नहीं है उस के लिए रोड पर कहीं पानी पीने के लिए ब्यवस्था ही नहीं है। इसलिए जहां जहां मोलम्बर जगे हुए हैं वहां वहां पाइप बैठा दिया जाय।

श्री सिकन्दर बकत : मैं यह धर्ज कर रहा हूँ और कर चुका हूँ कि जनता क्वनमेंट की पूरी चेष्टा है कि बड़े शहरों से घाबादी का दबाव कम होना चाहिए और उम का सब से बड़ा सबक यह है कि हर जगह पानी महदूद तौर पर मुहैया है। ना-महदूद पानी की क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए जरूरत है कि विल्ली में और हर बड़े शहर में घाबादी के दबाव को रोका जाय। लेकिन मैं धाप की इत्तिना के लिए धर्ज करूंगा कि एक प्लान्ट बड़ा सग चुका है और एक बड़ा प्लान्ट बहुत जल्दी पानी का सक्ने वाला है। यह ठी मैंने कुछ हाउर्स के बारे में धाप के सामने बाँठे रखी।

अपनी बात मैं यह रखना चाहता हूँ जिस के मुतालिक हमारे बहुत सारे साथी काफी एक्सप्राइज थे—रिहैबिलिटेशन का मामला। यह बहुत नाचुक मसला है और मैं जो लब्ज भी जवान पर धाज तक इस सम्मानित सदन के सामने लाया हूँ उस को बहुत एह्तियास से मैंने जवान से निकाला है। अब भी मैं चाहूँगा कि कुछ हकीकत की तरफ धाप की तकज्जह दिलाऊँ। यह न समझिएगा कि हम बिलकुल हार्डलेस हो गए हैं। अपने मुक्त में जिन लोगों के धा जाने के बाद हम ने जिन को धपना मान लिया है, हिन्दुस्तानी मान लिबा है उन की तरफ के हमने धाँख बन्ध कर ली है ऐसा मत समझिएगा। लेकिन हकीकत को जरा समझिएगा। रिहैबिलिटेशन का जो लब्ज है इस के मानी हम ने कभी पूरे तरीके से समझे हैं? क्या किसी एक ऐसे घादमी को जिन का धपना छोटे से छोटा घर छिन चुका हो, जो उस को छोड़ने पर मजबूर किया गया हो क्या उस को सही माने में रिहैबिलिटेट किया जा सकता है? रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा लब्ज है। कुछ जिक्र हुआ यहाँ पंजाब से धाप हुए भाइयों का मेरा कहना यह है कि हमारे कुछ मुसोबतजवा साथी पंजाब से धाप हों, सिंध से धाप हों, या बंगाल से धाप हों, बाक्या यह है कि कोई दुनिया की हुकूमत रिहैबिलिटेशन लब्ज की मुकम्मिल तरजूमानी हो, उस की दावेदारी नहीं कर सकती। रिहैबिलिटेशन में मददगार हो सकती है। रिहैबिलिटेशन में जिन मकस को रिहैबिलिटेट होना है उस को धपनी कोशिश जोड़नी चाहिए। हुकूमत को उम के रिहैबिलिटेट होने में मददगार होना चाहिए। मैं क्या बताऊँ? धाप जरा एक बात की तरफ तकज्जह फरमायें। इसमें कोई शक नहीं कि हर वह मकस जिस को कि धपना घर किसी हासत में छोड़ना पड़ा है, हिन्दुस्तान के एक एक रहने वाले का यह हक है कि वह उस की तरफ तकज्जह करे और उस की तकनीकों को दूर करे। लेकिन दूसरी बात मैं यह धर्ज करूँगा कि क्या

हिन्दुस्तान में धीरे कोई धबादी ऐसी नहीं है जिनकी दशा उस से ज्यादा या उसनी ही खराब हो जितनी हमारे धाप हुए भाइयों की है ? लातादाद हैं वे ।

इन हजरत को, इन साथियों को जो दूसरे मुल्कों से परेशान हो कर धाप हैं जिन को हम धपना मान चुके हैं धीरे हिन्दुस्तानी मान चुके हैं, मैं उन्हें रिफ्यूजी नहीं कहना चाहता हूँ, उन को धीरे धपने मुल्क में रहने वाले गरीबों को हम धगर अलाहिदगी से नहीं देखना चाहते हैं, एक नजर से देखना चाहते हैं तो कोई बजह नहीं है कि एक नजर से न देखा जाय । मैं धाप को यकीन दिलाता हूँ कि इन भाइयों पर जिन के एक्साइट का जिक्र हुआ है उस में किसी पर कोई ज्यादाती नहीं थी । दिक्कत क्या थी धीरे मैं तो इसको एक सब से खबरदस्त ट्रेजरी मानता हूँ—जिन जमीनों को वे छोड़ कर गए हैं, वे जमीनें उस भूमि पर आलातरीन जमीनें होने वाली हैं धीरे बहुत जल्दी होने वाली हैं । जो हमारी इरीमिशन स्कीम्स मटकी हुई थीं, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल कर उनको जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर रहे हैं । धगर वह स्कीमें मुकम्मल हो गई तो तीन तीन फसलें देने के काबिल होंगी । जो टान्टे मुकरर किए गए थे रितीफ के धीरे लोन के वह दे दिए गए । धाप हजरत ने इस बीज को माना है कि जो इम्प्लीमेंट्स दिए गए उनको बेच दिया गया, जो बँस दिए गए वे उनको बेच दिया गया धीरे जो सोन्स दिये गये वे उनकी वापसी की कोई एक्को उनसे नहीं हो रही है । लोग वहाँ से चले गए । धाप मुझे बतायें, क्यों गए । मैं धापसे कह रहा हूँ, सायद सुनने में तकलीफ हो, लेकिन हमें रिट्रैबिलिटेड करने के लिए धपने धापको रिट्रैबिलिटेड करने के लिए धपना मददगार खुद भी होना पड़ेगा । धाप इस बीज की तरफ एक्जहू दें । मैं धापसे हाथ जोड़ कर, दस्तबस्ता धन्य कल्या

कि भगवान के लिए उनके मददगार बन धीरे धाप उनको बतायें कि वे इन जगहों से न जायें । यह जगहें जन्त बनने वाली हैं । वेस्ट बंगाल की तकलीफ दुरस्त है, वे नयी धाबादी का दबाव से सके यह उनके लिये मुमकिन नहीं है । वे वेस्ट-बंगाल गये, उनको लाने की कोशिश की गई, तो रास्ते में ट्रेन छोड़कर चले गये—धब क्या तरीका हो । क्या खबरदस्ती लायें—उठा कर । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको धाप ऐसी प्राबलम बनाने की कोशिश न करें, जिसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही साल्व कर सके । मैं कहता हूँ—यह एक स्पूमन प्राबलम है, जिसमें हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी धाबादी शामिल हैं । हम सभी को मिल कर इसे हल करना चाहिये । इससे सिबासी फायदा नहीं उठाना चाहिये । मैं धापको यकीन दिलाता चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कैलस नहीं है, गवर्नमेंट कोई तरीका खरर मुकरर करना चाहती है । उस में धाप लोगों को हमारा मददगार बनना पड़ेगा । मसलन धण्डमान की किस्सा है । मैं धाप तक ईमानदारी से कन्वीव नहीं कर सका—कि 41 लाख रिफ्यूजीज में से 75 हजार को वहाँ रिट्रैबिलिटेड करना चाहिये, ऐसा छप हुआ था—जो माननीय सदस्य ने कहा—लेकिन मैं समझता हूँ कि यह दुस्त नहीं है । वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दो-ढाई हजार फॉमिलीज को रिट्रैबिलिटेड किया जा सकता था, पूरे रिफ्यूजीज को वहाँ से जाकर बसाया नहीं जा सकता । जनता गवर्नमेंट के धाने के पहले जो धोरिजिनल कमिटेमेंट था, वह दो-ढाई हजार फॉमिलीज का था, लेकिन 8 ली के करीब फॉमिलीज बसा दी गई । वहाँ पर एक सवाल यह पैदा हुआ कि इको-नाजिकल बँसेस डिस्टर्ब हो जायगा । दूसरा सवाल यह पैदा हुआ—कार बेरिष-रीजन्ड एक्स-सर्विच-मेन को वहाँ बसाना है । तीसरा सवाल सवाल—धण्डमान की धोरिजिनल धाबादी का है, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं ।

[श्री सिकन्दर बख्त]

में जानना चाहता हूँ—घर घर घण्टमान में जमीन रिक्लेम की जाय, तो वह ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजीज को जरूर दी जाय, लेकिन क्या जो वहाँ के घोरिजिनल लोग हैं—उनका उस पर कोई हक नहीं है ? उनके लिये कुछ न किया जाय ? लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि जो बुनियादी बात डार्ड हदार्ड फॉर्मिलीज की थी, उस में 8 सौ को बसाया जा चुका है। इससे ज्यादा उसका दायरा बसीध नहीं है, 41 लाख को वहाँ नहीं बसाया जा सकता है। इसलिये हर मौके पर घण्टमान का उस तरह से जिक्र करना कि ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजीज को वहाँ भेज दिया जाय, तो कोई प्राबल्य बाकी नहीं रहेगी—यह ठीक नहीं है। इसलिये जो गवर्नमेंट बे कमिट किया है, उस के मुताबिक 9621 फॉर्मिलीज रह गई हैं। कैम्पस हम ने डिस्कंबैंड कर दिये हैं और जल्दी से जल्दी इरियेशन स्कीम के पूरा होते ही इनको दोबारा बसाना चाहते हैं। इसलिए भी करना चाहते हैं कि 1971 के पाकिस्तान और हिन्दुस्तान कान्फिडेंट के दौरान जो 60 हजार रिफ्यूजीज सिन्धी हिन्दुस्तान में आ गये थे, मुझे ठीक फिलाल तो बाध नहीं, 50 हजार के करीब राकस्तान के कैम्पों में रखे गये थे और 10 हजार बुजरात में रखे गये थे। वे कैम्पस चले आ रहे हैं। हर साल सिफं उन कैम्पों की मेन्टेनेन्स पर 250 लाख रुपया सर्फ हो रहा है। बाखिर यह पब्लिक-फण्ड है, हम लोग जो वहाँ हुकूमत में धाते हैं, हमारे लिये यह रुपया प्रमानत है, इस तरह से इसको खर्च करने का किसी को हक नहीं है। वे लोग दुआ मांग रहे थे कि ये लोग वापस चले जायें और इस तरह से 250 लाख रुपया सालाना उन 60 हजार रिफ्यूजीज पर खर्च किया गया, इतने रुपये से तो उन सारे रिफ्यूजीज को रिविबिलिटेड किया जा सकता था, लेकिन वे कैम्पस धाज तक कायम रहे। अब हमने स्कीम बनाई है कि उनको बल्ड से बल्ड रिविबिलि-

टेड किया जाय। लेकिन इस तरह से पब्लिक फण्ड को नष्ट करने का हक किसी भी हुकूमत को नहीं है।

वे सब बातें मैंने रिविबिलिटेसन के बारे में धाज की हैं। मेरे क्वाल में अब कोई ऐसी बात नहीं रही है कि जिसकी डिटेल में जाने की जरूरत हो।

श्री राम किसन (भरतपुर) : मेकों के बारे में धापने कुछ नहीं बताया।

श्री सिकन्दर बख्त : मेकों का मामला रिविबिलिटेसन से सीधे तोर से जोड़ना गलत है, यह रिविबिलिटेसन का मसला नहीं है, इस लिए यह मेरी मिनिस्ट्री का मसला नहीं है।

श्री राम किसन : यह धापकी मिनिस्ट्री का ही मामला है।

श्री सिकन्दर बख्त : धाप मुझे निजी तोर पर मिल लें, मैं धापको बतलाने की कोसिस करूंगा। मैं धाप सब साहबान का बहुत मुकाम्बार हूँ, मैंने धापका इतना सभय किया, मैं धासा करता हूँ कि मेरी बुजारिमात को यह सदन मंजूर करेवा।

SHRI SAUGATA ROY: One clarification.

MR. CHAIRMAN: He has covered all the points.

SHRI SAUGATA ROY: He has made an emotional appeal. I appreciate his emotion, but he has not said whether he is going to give any fresh help to West Bengal in order to solve the residual problem. हम इस के बारे में सुनना चाहते हैं, धाम भाषण तो हम सुना ही करते हैं।

SHRI SIKANDAR BAKHT: This question has been put to me a number of times, and I have given the mind of the Government.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account

shown in the fourth Column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day

of March, 1979, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 89 to 93 relating to the Ministry of Works and Housing." *The motion was adopted.*

Demands for grants, 1978-79 in respect of the Ministry of Works and Housing voted by Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16-3-1978		Amount of Demand for Grant voted by the House	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING					
89.	Ministry of Works and Housing	19,40,000		97,00,000	
90.	Public Works	12,87,04,000	6,38,41,00	64,35,21,000	21,92,03,000
91.	Water Supply and Sewerage	10,45,00,000		52,25,00,000	
92.	Housing and Urban Development	2,58,31,000	6,13,84,000	12,91,55,000	30,69,18,000
93.	Stationery and Printing	5,66,26,000		28,31,30,000	

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidate Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will

come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1979, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 82 to 84 relating to the Ministry of Supply and Rehabilitation."

The motion was adopted

Demands for Grants, 1978-79 in respect of the Ministry of Supply and Rehabilitation voted by Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16-3-1978		Amount of Demand for Grant voted by the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION					
82.	Department of Supply	4,09,000		20,45,000	..
83.	Supplies and Disposals	1,26,43,000		6,32,16,000	..
84.	Department of Rehabilitation	4,63,28,000	2,16,20,000	23,16,40,000	10,81,02,000

18.40 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS—contd.

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

MR. CHAIRMAN: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 11 to 13 relating to the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation for which six hours have been allotted. Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Those cut motions will be treated as moved.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charge that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1979, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 11 to 13 relating to the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation."

Demands for Grants, 1978-79 in respect of Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16-3-1978		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION					
11.	Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation	29,81,000	..	1,49,04,000	
12.	Foreign Trade and Export Production	49,18,92,000	67,60,90,000	245,94,63,000	338,04,52,000
13.	Civil Supplies and Cooperation	6,25,38,000	3,67,57,000	31,28,92,000	18,37,83,000

*Moved with the recommendation of the President.